https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'13 शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण'

वर्ष-13, अंक-14 16-31 जुलाई, 2018 (पाक्षिक) ₹20

'कश्मीर से कन्याकुमारी तक विजय पताका लहराएं'

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि

जीएसटी के एक वर्ष पर विशेष

'देश के स्वर्णिम इतिहास पर काला धब्बा है आपातकाल'

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जनसंघ संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जयंती (6 जुलाई) पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, साथ में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल

पुणे (महाराष्ट्र) में तुकाराम महाराज पालखी यात्रा के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस

वाराणसी (उ.प्र.) में सोशल मीडिया स्वयंसेवकों को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

तिरुवनंतपुरम (केरल) में 6 संसदीय क्षेत्रों के शक्ति केन्द्रों के प्रभारियों की बैठक के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

'संपर्क फॉर समर्थन'

तिरुवनंतपुरम (केरल) में विवेकानन्द केंद्र के अध्यक्ष एवं प्रख्यात विचारक श्री पी. परमेश्वरन से भेंट करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत हरिद्वार (उत्तराखंड) में भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को साहित्य भेंट करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के दौरान श्री बाबासाहेब पुरंदरे के पुणे (महाराष्ट्र) स्थित निवास पर उन्हें मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों पर केंद्रित पुस्तिका देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 जुलाई को आगरा, उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 बेमिसाल वर्ष की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबोधन की शुरुआत करते हुए...

वैचारिकी

विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही मानव मूल्यों की रक्षा संभव 17

श्रद्धांजलि

बाल गंगाधर तिलक 20

लेख

जीएसटी से जुड़े अनुभव 21

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बढ़ते कदम 23

अन्य

'किसान हित में क्रांतिकारी कदम' 10

अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या 70 प्रतिशत बढ़ी 14

'एबार, पश्चिम बंगो' 25

प्रशिक्षण महाभियान बैठक 26

आपातकाल देश के स्वर्णिम इतिहास पर काला धब्बा है: नरेन्द्र मोदी 27

देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय है आपातकाल : अमित शाह 28

'सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने गरीबों, दलितों को संकट से जूझने और... 30

अब 'बेल गाड़ी' के नाम से जानी जाती है कांग्रेस पार्टी : नरेन्द्र मोदी 31

प्रधानमंत्री की संत कबीर नगर जिला स्थित मगहर की यात्रा 32

डॉक्टर परिवार के मित्र सरीखे हैं: नरेंद्र मोदी 33

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

व्यंग्य चित्र 04

11 शक्ति केंद्र की शक्ति को बूथ तक ले जाना है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने गोल्डन बीच रिसॉर्ट, चेन्नई में आयोजित तमिलनाडु भारतीय जनता...

13 'माकपा को केरल से उखाड़ फेंकना भाजपा का लक्ष्य'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी का मिशन केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम...

08 खरीफ की हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना

किसानों को फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना दाम दिलाने के वादे को पूरा करते हुए...

15 अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 11.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने 1 जुलाई को प्रथम जीएसटी दिवस मनाया। जीएसटी...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने किसानों के श्रम को मान नहीं दिया। कांग्रेस ने चिंता की तो सिर्फ एक ही परिवार की, किसानों के लिए अवैज्ञानिक तरीके से बेसिर-पैर की योजनाएं बनाईं। पिछले चार वर्षों में स्थिति बदली है। एनडीए सरकार किसानों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

@AmitShah

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाना चाहती है जिन तक आजादी के 70 साल बाद भी और कांग्रेस की चार पीढ़ियों के शासन के बावजूद विकास नही पहुंच सका।

@myogiadityanath

उत्तर प्रदेश के अन्दर विकास की अपार सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर सेक्टर में प्रदेश सरकार भरपूर सहयोग करने को तैयार है। बड़े उद्योगों को लगाने के लिए प्रदेश सरकार की नीति के अंतर्गत जो सुविधाएं होंगी, उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रदेश के अंदर उद्यम लगाने की जो सबसे पहली गारंटी है, वो है सुरक्षा की।

facebook

प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हमने पिछले साढ़े चार वर्षों में कई ऐसे प्रभावी कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाये हैं जिनसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आमजन तक सुलभ हुई है और घर के पास ही लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज निःशुल्क मिलने लगा है। — **वसुंधरा राजे**

हमारे प्रदेश के गरीब लोगों के जीवन स्तर में मूलभूत बदलाव लाने के उद्देश्य से हमने जनकल्याण योजना (संबल) बनाई है। अनेक तरह के लाभ हम इस योजना के अंतर्गत प्रदान कर रहे हैं। मजदूर अब मजबूर नहीं रहेगा। सभी गरीब बंधुओं से मेरी अपील है कि इस योजना में पंजीयन कराएं और लाभ उठाएं। — **शिवराज सिंह चौहान**

एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जटिल कर प्रणाली की जगह GST लागू कर आर्थिक सुधार की दिशा में कठोर लेकिन सार्थक निर्णय लिया था। पूरे देश में लागू समान कर पद्धति से राज्यों के बीच व्यापारिक सीमाएं समाप्त हुई हैं और व्यापार क्षेत्र विस्तृत हुआ है। — **डॉ. रमन सिंह**

व्यंग्य चित्र

साभार : सोशल मीडिया

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन

आज जबकि पूरा देश जीएसटी लागू होने के एक वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है, मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भारी बढ़ोत्तरी कर किसानों को खुशियों की एक और सौगात दी है। जैसा कि बजट 2018–19 में घोषणा हुई थी, इस निर्णय से किसानों को अब अपने लागत का डेढ़–गुणा अधिक मूल्य मिलना सुनिश्चित हो गया है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे तथा किसानों के घर खुशहाली आयेगी। यह पहली बार है कि किसानों की समस्याओं के दूरगामी समाधान के लिये गंभीर प्रयास हो रहे हैं, जिससे देश के अन्नदाताओं के मन में आत्मविश्वास बढ़ा है। एसएसपी में अब तक की सर्वाधिक बढ़ोत्तरी कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट किया है तथा दशकों से उपेक्षित कृषि क्षेत्र में आशा की किरण जगायी है। ऐसा पहली बार है कि किसी सरकार ने घोषित रूप से 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिये बहुआयामी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कमर कसी हो। लागत से डेढ़ गुणा ज्यादा मूल्य इस दिशा में एक बड़ी छलांग है।

कृषि हमारे समाज की रीढ़ रही है। किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से न केवल देश को खाद्य सुरक्षा दी है बल्कि इस क्षेत्र में देश का एक बड़ा हिस्सा रोजगार भी पाता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस शासन में इस क्षेत्र में प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं हुआ तथा निरंतर उपेक्षा एवं गलत नीतियों के कारण लोग इस क्षेत्र से पलायन को बाध्य हुए। कृषि न केवल घाटे का सौदा बनकर रह गई बल्कि इस स्थिति से लोगों को उबारने के लिये दूरगामी नीति भी नहीं बनाई गई। किसानों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया।

यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे तथा किसानों के घर खुशहाली आयेगी। यह पहली बार है कि किसानों की समस्याओं के दूरगामी समाधान के लिये गंभीर प्रयास हो रहे हैं, जिससे देश के अन्नदाताओं के मन में आत्मविश्वास बढ़ा है। एसएसपी में अब तक की सर्वाधिक बढ़ोत्तरी कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट किया है तथा दशकों से उपेक्षित कृषि क्षेत्र में आशा की किरण जगायी है।

यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय को 2022 तक दुगुनी करने के लक्ष्य से अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि बीमा योजना से किसानों की ताकत बढ़ी है और अब वो किसी भी जोखिम को उठाने के लिये तैयार है और नये प्रयोग करने का साहस कर रहे हैं। 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' जैसे कार्यक्रम से किसान अब अपनी मिट्टी की प्रकृति के अनुसार फसलों का चयन करने में सक्षम हैं। 'पर ड्रॉप–मोर क्रॉप' की योजना से किसान अब पानी की हर बूंद का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। बड़ी संख्या में सिंचाई परियोजनाएं जो वर्षों से अवरूद्ध थीं, अब या तो पूरी कर ली गई हैं या पूर्ण होने वाली हैं। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजटों में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश करने से कृषि क्षेत्र मजबूत हुआ है और ग्रामीण परिवेश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

यह बड़ी विडम्बना है कि कुछ लोग समर्थन मूल्य की ऐतिहासिक वृद्धि पर भी आधारहीन बातों से इस कदम की भी आलोचना करने से नहीं चूकते। ये वही लोग हैं जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सरकार अपने बजट के वादे को पूरा कर पायेगी, अब ये कह रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। जो लोग किसानों की स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहाते थे अब कह रहे हैं कि धान पर इतना अधिक समर्थन मूल्य देना बेमानी है। अब एक नया तर्क भी गढ़ा जा रहा है कि समर्थन मूल्य बढ़ाने से कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। ये वही लोग हैं जो समस्याओं की बात तो करते हैं परन्तु यदि समाधान सामने आता है तब समाधान को ही समस्या बताने लगते हैं। इस तरह की बेतुकी आलोचनाओं से मोदी सरकार द्वारा किये गये कार्यों को जन–जन तक पहुंचने से नहीं रोका जा सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता से देश का हर गरीब, किसान, वंचित वर्ग पूरी तरह से परिचित है। केवल एक ईमानदार एवं प्रतिबद्ध सरकार ही समर्थन मूल्य में इतनी भारी वृद्धि कर सकती थी एवं जनकल्याण के इतने कार्यक्रम चला सकती थी। मोदी सरकार की हर योजना एवं कार्यक्रम दूरदृष्टिपूर्ण हैं तथा दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। जिन लोगों ने जीएसटी की आलोचना की थी, आज उसके लाभ जब देश एवं हर व्यक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, तब ये आलोचक निरूत्तर हैं। आज जो समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की आलोचना कर रहे हैं वे बाद में स्वीकारेंगे कि इस एक कदम से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 जुलाई को आगरा, उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 बेमिसाल वर्ष की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि यदि आज देश में जनता की पूर्ण बहुमत की सरकार देश के विकास एवं आम जनता के कल्याण के लिए निर्णयक फैसले ले रही है तो इसका यश सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है।

श्री शाह ने कहा कि आज बहुत कम ही ऐसी पार्टियां बची है जो परिवारवाद अथवा जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं करती। आज लगभग हर पार्टी का किसी न किसी जाति या परिवार विशेष के लिए काम करना ही उद्देश्य है। ऐसी पार्टियां परिवार और जाति विशेष तक ही सीमित होकर रह गई है, उन्हें राष्ट्र के विकास अथवा देश के आम नागरिक के कल्याण की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश के लगभग 1650 राजनीतिक पार्टियों में केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो किसी जाति अथवा परिवार के आधार पर नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर चलती है और जिसका एकमात्र उद्देश्य समग्र हिन्दुस्तान का कल्याण है। यही भारतीय जनता पार्टी और देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों के बीच का अंतर है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 1950 से लेकर आज तक की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अमूल्य दर्शन 'अंत्योदय' की विचारधारा के आधार पर ही चली है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को विकास की प्रथम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बराबर लाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार, दोनों ने अंत्योदय के सिद्धांत पर विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की सफल शुरुआत की है।

वाराणसी

'सरकार की योजनाओं को समाज की अंतिम इकाई तक पहुंचाएं'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि मिशन 2019 के चुनावी रचना में साइबर योद्धाओं की बड़ी भूमिका होगी। इनके द्वारा तैयार पृष्ठभूमि से ही मिशन की सफलता सुनिश्चित होगी। गत 4 जुलाई को वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फसिलटी सेंटर में सोशल मीडिया सेल से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि हर दौर में योद्धाओं की आवश्यकता रहती है और आज का दौर साइबर का है और इससे जुड़े लोग साइबर योद्धा हैं। श्री शाह ने कहा कि सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी और मनमोहन सरकार की योजनाओं का तुलनात्मक विवरण और उसके निष्कर्ष पर फोकस किया जाना चाहिए। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि उनकी (कांग्रेस सरकार) कथनी और करनी में कितना अंतर था और हमने किस हद तक इसे कम कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि आईटी सेल को सरकार की योजनाओं को समाज की अंतिम इकाई तक पहुंचाने का काम ठीक उसी तरह करना होगा, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री किया करते हैं। श्री शाह ने कहा कि तमाम लोगों तक बड़े नेताओं द्वारा सरकार की उपलब्धियों का परिचय दिया जा चुका है और अब यह जिम्मेदारी साइबर योद्धाओं की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया के स्वयंसेवकों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी की विजय पताका लहराने का आह्वान किया।

मिर्जापुर

'गांव-गांव जाएं और नए लोगों को पार्टी से जोड़ें'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 जुलाई को मिर्जापुर काशी, अवध और गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर लोगों से जुड़ने को कहा। श्री शाह ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होता है। आप लोग गांव-गांव जाएं और नए लोगों को पार्टी से जोड़ें। उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ ही लाभ दिलाएं। पार्टी का नारा सबका साथ-सबका विकास है तो उसको पूर्ण करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीस जिलों के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं, विस्तारकों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों, मंत्रियों को सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडेय और अनेक मंत्री भी उपस्थित थे।

संयुक्त विपक्ष की अवधारणा पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि बिना किसी कारण के कोई इकट्ठे नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेन्द्र मोदी के नाम का भय इतना है कि आज एक-दूसरे को मारने पर धुर-विरोधी भी एक साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं तो दूसरी ओर लगभग सारा विपक्ष। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नारा है - 'मोदी हटाओ' जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का नारा है - भ्रष्टाचार, गरीबी और अव्यवस्था हटाओ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जहां देश से भ्रष्टाचार, गरीबी और अव्यवस्था को हटाना चाहते हैं, वहीं विपक्ष देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को हटाना चाहता है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाना चाहती है जिन तक आजादी के 70 साल बाद भी और कांग्रेस की चार पीढ़ियों के शासन के बावजूद विकास नहीं पहुँच सका। उन्होंने कहा कि पहली बार देश के हर गरीब में आशा और विश्वास का संचार हो रहा है कि आज देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके उत्थान के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चार सालों में लगभग चार करोड़ गरीब माताओं को गैस कनेक्शन दिए, साढ़े सात करोड़ शौचालयों का निर्माण किया, 31 करोड़ लोगों के बैंक एकाउंट खोले, 18 करोड़ बच्चों का मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित किया, 12 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक की योजना से स्वरोजगार के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराये और आजादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित लगभग 19 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई। उन्होंने कहा कि 2022 तक देश का ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां बिजली न हो और कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिनके सिर पर अपनी छत न हो।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के नए पैरामीटर स्थापित किये हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति में भी व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के काले दौर में नौकरी और विकास के लिए केवल जाति विशेष देखी जाती थी, यहाँ तक कि एफआईआर भी धर्म विशेष और जाति विशेष देखकर दाखिल हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले पुलिस आपराधिक तत्वों से डरती थी, आज योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का डंडा इस तरह से चल रहा है कि अपराधी यूपी छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई है, किसानों की 35 हजार करोड़ से अधिक की कृषि ऋण माफी की गई है।

उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस के बेमेल गठजोड़ पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भले ही बहन जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इकट्ठे आ जाएँ लेकिन 2019 के लोक सभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की यूपी में सीट 73 से 74 होगी, 72 नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनमें से किसी के पास भी भाजपा को अकेले हराने का दम बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वालों का समर्थन कदापि नहीं कर सकती, वह गरीबों की झोपडी की जगह अपने बंगले की चिंता करने वालों का समर्थन कभी भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ना है और उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि बहुत समय बाद यूपी की जनता को एक साफ़-सुथरी सरकार मिली है और ऐसा मुखिया मिला है जिसके लिए सूबे की जनता ही उनका परिवार है। ■

खरीफ की हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ा

किसानों को फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना दाम दिलाने के वादे को पूरा करते हुए भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने खरीफ की हर फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भारी बढ़ोत्तरी की है।

दरअसल, भाजपा ने किसानों से साथ वादा किया था कि वह किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाएगी। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने इस साल पेश किए गए बजट में इस वादे को पूरा करने की घोषणा भी की। साथ ही, बजट 2018-19 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए जरूरी कृषि नीति में बदलाव करने का संकेत दिया गया। बजट में बेहतर आय सृजन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया।

किसानों की आय बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से संबंधित समिति ने 4 जुलाई को 14 खरीफ फसलों के एमएसपी के प्रस्तावों को स्वीकृत किया। धान (सामान्य किस्म) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ाकर 1,750 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान (ग्रेड ए) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ाकर 1,750 रुपये प्रति क्विंटल कर किया गया। इसी तरह कपास (मध्यम आकार का रेशा) का एमएसपी 4,020 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,150 रुपये प्रति क्विंटल और कपास (लंबा रेशा) का एमएसपी 4,320 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति क्विंटल पर कर दिया गया।

अरहर का एमएसपी 5,450 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,675 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग का एमएसपी 5,575 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,975 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का एमएसपी 5,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,600 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। गौरतलब है कि विपणन वर्ष 2016-17 की खरीद के आंकड़ों के हिसाब से धान का एमएसपी बढ़ाने से खाद्य छूट पर 11 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

यही नहीं, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं अन्य प्राधिकृत राज्य एजेंसियां पोषक अनाज सहित अन्य अनाजों के लिए किसानों को मूल्य समर्थन जारी रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), एफसीआई, स्मॉल फारमर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) एवं अन्य प्राधिकृत केंद्रीय एजेंसियां दलहन एवं तिलहन की खरीदारी जारी रखेंगे। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास के समर्थन मूल्य की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगा।

दलहन की खेती को बढ़ावा दिए जाने से भारत को पोषण असुरक्षा से निपटने, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार दलहन के एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों की प्रति एकड़ आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसके अलावा एमएसपी में वृद्धि से तिलहन के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, इससे भारत को अपना आयात बिल घटाने में भी मदद मिलेगी। पोषक अनाजों के न्यूनतम मूल्य वृद्धि से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में सुधार होगा।

किसानों के लिए सरकार की प्रमुख पहल

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के अलावा सरकार ने किसानों के अनुकूल कई अन्य पहल की है जो इस प्रकार हैं:

- किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दरें काफी हैं– सभी

भारत सरकार द्वारा खरीफ 2018–19 में विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य में प्रति कुंतल बढ़ोत्तरी का विवरण

फसल	घोषित समर्थन मूल्य प्रति कुंतल (2018–19)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (रू.में)
धान (सामान्य)	₹1750	₹200
धान (ग्रेड–ए)	₹1770	₹180
ज्वार (हाईब्रिड)	₹2430	₹730
ज्वार (मालडण्डी)	₹2450	₹725
बाजरा	₹1950	₹525
रागी	₹2897	₹997
मक्का	₹1700	₹275
अरहर (तुअर)	₹5675	₹225
मूँग	₹6975	₹1400

फसल	घोषित समर्थन मूल्य प्रति कुंतल (2018–19)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (रू.में)
उर्द	₹5600	₹200
मूँगफली	₹4890	₹440
सूरज मुखी	₹5388	₹1288
सोयाबीन	₹3399	₹349
तिल	₹6249	₹949
कुसुम	₹5877	₹1827
कपास (मध्यम रेशे वाले)	₹5150	₹1130
कपास (लम्बे रेशे वाले)	₹5450	₹1130

खरीफ फसलों के लिए यह कुल बीमित रकम का 2 प्रतिशत, सभी रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और नकदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। साथ ही मोबाइल फोन एवं रिमोट सेंसिंग जैसी स्मार्ट प्रौद्योगिकी के जरिए तत्काल आंकलन एवं दावों का जल्द निपटारा।

▸ सरकार ने फसल बीमा के लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है जो किसानों को उनके क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। साथ ही, वे इसके जरिए अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की गणना कर सकेंगे।

▸ सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के क्रम में एक साझा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ 585 विनियमित बाजारों को एकीकृत करने के उद्देश्य से 'नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट' (एनएएम) के तहत देश भर में इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक योजना भी शुरू की है। प्रत्येक राज्य को तीन प्रमुख सुधारों की शुरूआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति, पूरे राज्य में एकल लाइसेंस की वैधता और बाजार में प्रवेश के लिए एकल शुल्क शामिल है। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य तलाशने में भी मदद मिलेगी। 23 मार्च, 2018 तक 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 बाजारों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म से पहले ही जोड़ा जा चुका है।

▸ मौजूदा एपीएमसी के विनियमित बाजार दायरे के बाहर किसानों को बाजार का विकल्प मुहैया कराने के लिए सरकार एक नया कानून एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग (प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2017 भी तैयार किया है।

▸ देश भर में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक दो साल बाद इन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। यह कार्ड भूमि की उर्वरता की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा और मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह देगा। 25 जून, 2018 तक 15.14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

▸ परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत सरकार जैविक कृषि और जैविक उत्पादों के लिए संभावित विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

▸ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 'हर खेत को पानी' के लिए सिंचाई कवरेज में विस्तार के उद्देश्य के साथ लागू किया गया है। इसके तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' के उद्देश्य के साथ जल के उपयोग की कुशलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्रोत के सृजन, वितरण, प्रबंधन एवं विस्तार संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए आद्योपांत समाधान उपलब्ध कराया जा रहा है।

▸ सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दलहन जैसे फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

▸ समर्पित ऑनलाइन इंटरफेस ई-कृषि संवाद किसानों की समस्या के लिए प्रत्यक्ष एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध करा रहा है।

▸ सरकार किसान उत्पादक संगठन तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। बजट 2018-19 के तहत किसान उत्पादक संगठनों को अनुकूल कराधान उपलब्ध कराया गया है, ताकि किसानों को इनपुट जरूरतों, कृषि सेवाओं, प्रसंस्करण एवं बिक्री परिचालन में मदद मिल सके।

▸ सरकार ने दालों का एक बफर स्टॉक भी तैयार किया है और मूल्य स्थिरीकरण फंड (पीएसएफ) के तहत दालों घरेलू खरीदारी भी कर रही है, खासकर उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टि से बजट 2018-19 में संकेत दिया गया था कि केवल एमएसपी में वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को घोषित एमएसपी का पूरा फायदा मिलना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि कृषि उत्पादों का मूल्य घोषित एमएसपी से कम होगा तो सरकार को एमएसपी दर पर खरीदारी करनी चाहिए अथवा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें घोषित एमएसपी मिल सके। केंद्र एवं राज्य सरकारों से परामर्श के साथ नीति आयोग इसके लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करेगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उपयुक्त मूल्य मिल सके।

▸ महिला किसानों के लिए पुस्तिका 'फार्म वुमेन फ्रेंडली हैंड बुक' में विशेष प्रावधानों एवं पैकेज सहायता की जानकारी दी गई है। महिला किसान कृषि विभाग की विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं का फायदा उठा सकती हैं।

▸ इस सब उपायों के साथ सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। ■

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक वृद्धि

'किसान हित में क्रांतिकारी कदम'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 जुलाई को मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और किसानों के हित में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई दी और मोदी सरकार के इस कदम को किसानों की माली हालत में सुधार लाने हेतु क्रांतिकारी कदम करार दिया।

श्री शाह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की कैबिनेट कमिटी की बैठक में खरीफ फसलों की एमएसपी को उनके लागत मूल्य से डेढ़ गुना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जो कि देश के किसानों के उत्थान में निर्णायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि कई खरीफ फसलों की एमएसपी में तो लगत मूल्य से डेढ़ गुने से भी अधिक की बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी एवं देश के करोड़ों किसानों की ओर से किसानों की स्थिति में सुधार लाने के इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी कैबिनेट के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई, अभिनंदन और साधुवाद देता हूँ। यह न केवल किसानों की उपज के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करेगा बल्कि उनके जीवन में भी गुणात्मक सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के लिए प्रभावी फसल बीमा योजना और अब MSP में यह ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी, मोदी सरकार की "सबका साथ-सबका विकास" की दिशा में कटिबद्धता को प्रमाणित करती है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश की आजादी के बाद से ही किसानों की यह मांग थी कि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए देश में कई किसान आंदोलन हुए और कई किसानों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी लेकिन कांग्रेस एवं उनके सहयोगियों की किसी भी सरकार ने फसल की एमएसपी को लागत मूल्य से डेढ़ गुना करने का साहस नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी में 50% या उससे अधिक की वृद्धि कर किसानों की सात दशकों की मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों के विपरीत जिनकी योजनायें केवल फाइलों और उनके घोषणापत्रों पर ही रह जाती थी यह मोदी सरकार अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सफल हुई है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के गठन के साथ ही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के हित में एक-के-बाद-एक कई अहम् फैसले लिए हैं, साथ ही किसानों की भलाई के लिए किये गए अपने वादों को अक्षरशः पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यूरिया की नीम कोटिंग की गई जिससे यूरिया की कालाबाजारी पूर्णतः रुक गई और किसानों के लिए यह सहज रूप से उपलब्ध हो पाई। इसके पश्चात् खादों/उर्वरकों के मूल्य में कटौती की गई। प्रभावी प्रधानमंत्री फसल बीमा के रूप में 'सुरक्षित फसल, समृद्ध किसान' की व्यापक अवधारणा को मूर्त्त रूप दिया गया, इसमें और सुधार की प्रक्रिया में शुरू है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी सुलभ कराया गया है और सालों से लटकी हुई सिंचाई परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। स्वायल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल नुकसान के कारण मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि ये सभी निर्णय बताते हैं कि मोदी सरकार किसानों की भलाई, उनके उत्थान एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए कृतसंकल्पित है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की माली हालत में सुधार, कृषि को बचाने और गाँवों को सक्षम बनाने में एमएसपी में डेढ़ गुने की वृद्धि मील का पत्थर साबित होगी। इससे देश के करोड़ों किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा, छोटे किसानों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फसलों की एमएसपी में डेढ़ गुने की वृद्धि कर किसानों को उनका अधिकार दिया है जिससे इन्हें वंचित रखा गया था।

श्री शाह ने कहा कि देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन दीपावली की तरह है क्योंकि 70 सालों से लंबित उनकी चिर-प्रतीक्षित मांग को मोदी सरकार ने पूरा कर किसानों के जीवन में रोशनी लाने का काम किया है। इससे किसानों की माली हालत तो सुधरेगी ही, साथ ही खेतिहर मजदूर की हालत में भी व्यापक सुधार होगा, गाँवों को भी ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी में डेढ़ गुने की वृद्धि किसान, खेतिहर मजदूर, गाँव - सभी के लिए एक मल्टी डायमेंशनल फायदा पहुंचाने वाला फैसला है जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनके केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हार्दिक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में बधुत बड़ा फैसला लिया है जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम परिणाम प्राप्त होंगे और किसानों की कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा। उन्होंने मीडिया बंधुओं से भी इस ऐतिहासिक निर्णय को देश के किसानों तक पहुंचाने की अपील की ताकि किसानों को उनका अधिकार प्राप्त हो सके। ■

शक्ति केंद्र की शक्ति को बूथ तक ले जाना है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 9 जुलाई को गोल्डन बीच रिसॉर्ट, चेन्नई में आयोजित तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के महा शक्ति केंद्रम एवं शक्ति केंद्रम के प्रभारियों के बैठक को संबोधित किया और उनसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट हो जाने का आह्वान किया। इस सम्मलेन में तमिलनाडु के हर शक्ति केन्द्रम से 15 हजार से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। श्री शाह ने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी की लोक सभा टोली और राज्य के लोक सभा प्रभारियों एवं पार्टी के विस्तारकों के साथ भी बैठक की।

तमिलनाडु की महान जनता से करबद्ध निवेदन करते हुए श्री शाह ने कहा कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस ऐतिहासिक सम्मेलन में तमिलनाडु और पुदुच्चेरी के हर शक्ति केंद्र के अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं, लगभग 15 हजार से अधिक भाजपा कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि तमिलनाडु में विपक्ष हमारा मजाक उड़ाता था कि राज्य में भाजपा है कहाँ? उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि विपक्ष को तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना है तो 2019 के लोक सभा चुनाव में ईवीएम में ढूंढ लें। उन्होंने कहा कि 2019 के लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी ताकत बन कर उभरने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विगत चार सालों में जो विकास की महान यात्रा शुरू हुई है, इससे देश के गाँव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवा एवं महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है और दुनिया में देश की मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोक-कल्याणकारी नीतियों के कारण देश के लगभग 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के जीवन में एक नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है और उन्हें आजादी के बाद पहली बार महसूस हो रहा है कि केंद्र में उनके लिए काम करने वाली सरकार है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने चार सालों के अपने कार्यकाल में तमिलनाडु के विकास को काफी प्राथमिकता दी है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियों पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में तमिलनाडु के विकास के लिए जितना काम नहीं हुआ, उससे अधिक कार्य मोदी सरकार ने 4 सालों में करके दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन की यूपीए सरकार के 10 वर्ष के शासन में डीएमके भी हिस्सेदार थी लेकिन 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को केवल 94,540 करोड़ रुपये दिए गए जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार द्वारा राज्य को 1,99,996 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, लगभग 104,000 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोत्तरी केंद्र की मोदी सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त केंद्र की विभिन्न परियोजनाओं में मोदी सरकार ने तमिलनाडु के लिए 135,000 करोड़ रुपये अलग से दिए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए लगभग 332 करोड़, चेन्नई मेट्रो के लिये 28 75 करोड़, चेन्नई मोनो रेल के लिए 3267 करोड़, 3200 किमी रेलवे लाइन के लिए 20,000 करोड़, 2017 के अकाल के लिए 1750 करोड़, वर्धा समुद्री तूफ़ान से प्रभावित लोगों के लिए 265 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के 1445 प्रोजेक्ट्स के लिए 3694 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 828 करोड़, मदुरै एम्स के लिए 1005 करोड़, तंजावुर और तिरूनेलवेली मेडिकल कॉलेज के लिए 250 करोड़, हैरिटेज सिटी डेवलपमेंट के लिए 45 करोड़, अमृत सिटी मिशन के लिए 4757 करोड़, सागरतट परियोजना के लिए 100 करोड़, नेशनल हाइवे के लिए 23700 करोड़, भारतमाला परियोजना के लिए 40500 करोड़, सेन्ट्रल रोड प्रोजेक्ट के लिए 2100

करोड़,इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ और पोर्ट के लिए 28,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर मोदी सरकार ने तमिलनाडु के लिए लगभग 5 लाख 10 हजार करोड़ रुपये चार सालों में देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, उन्होंने पहले तमिलनाडु की जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिर जब वे केंद्र में थे, तो उन्होंने राज्य के लिए क्या किया?

श्री शाह ने कहा कि परियोजनाओं में केंद्र द्वारा मिलनेवाली सहायता राशि के अतिरिक्त मुद्रा योजना में अकेले तमिलनाडु में लगभग 62,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गए, प्रधानमंत्री फसल बीमा के तौर पर लगभग 2400 करोड़ रुपये की क्लेम राशि वितरित की गई, लगभग एक करोड़ लोगों को स्वायल हेल्थ कार्ड वितरित किये गए, लगभग 17 लाख गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, जन-धन योजना के तहत लगभग 90 लाख खाते खोले गए, लगभग 28 लाख परिवारों को एलईडी बल्ब दिए गए और इन सबके अतिरिक्त अन्य छोटी-मोटी योजनाओं में अलग से अलग से 1370 करोड़ रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए 125 से अधिक योजनायें बनाई हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि हम इन सभी योजनाओं को तमिलनाडु में नीचे तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को राज्य में नीचे तक ले जाने में कुछ एनजीओ भी हमारी मदद कर रहे हैं, मैं उन सभी एनजीओ का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की यूपीए सरकार के 10 वर्षों में लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के घपले-घोटाले हुए थे, वहीं मोदी सरकार के चार सालों में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि देश के जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, वहां हमने प्रदेश को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बस, मुझे इस बात का दुःख है कि तमिलनाडु की गिनती सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले प्रदेशों में होती है। उन्होंने तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप राज्य में एक ऐसी सरकार के गठन के लिए एकजुट हो जाएँ जो तमिलनाडु से भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप राज्य में हर जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकें। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में से चुनावी भ्रष्टाचार को केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार ही ख़त्म कर सकती है और क़ानून और व्यवस्था की स्थिति भी भाजपा के सहयोग से बनने वाली सरकार ही सुधार सकती है।

श्री शाह ने कहा कि जिस प्रकार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, इस षड्यंत्र के खिलाफ भाजपा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमिल प्राइड को लेकर दुष्प्रचार शुरू किया जा रहा है। मैं तमिलनाडु की जनता को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु की भाजपा यूनिट तमिल प्राइड और तमिल भाषा के गौरव के लिए जितना कमिटेड है, उतनी कमिटेड कोई और पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष राज्य में तमिल भाषा की दुहाई देते हैं लेकिन जब ये केंद्र में सत्ता में थे तो तमिल भाषा में रेलवे की टिकट नहीं मिलती थी, जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब जाकर तमिल भाषा में रेलवे टिकट मिलने की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही हमारी नीति ऐसी है कि हर राज्य का गौरव भाजपा के गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। हर राज्य की भाषा को, स्थानीय भाषाओं को सम्मान देना और उसका प्रचार-प्रसार करना भाजपा की संस्कृति रही है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी भागीदार हो, उसी दिन से तमिल भाषा राज्य की सीमाओं को लांघकर देश भर में फैलेगी और पूरे देश में तमिल भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जो विकास की यात्रा चली है, इसे 2019 में भी आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं। ■

मदनलाल सैनी बने राजस्थान प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 29 जून को राज्यसभा सांसद श्री मदनलाल सैनी को भाजपा, राजस्थान प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री सैनी पूर्व विधायक और रा.स्व.संघ के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ में अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। ■

'माकपा को केरल से उखाड़ फेंकना भाजपा का लक्ष्य'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी का मिशन केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद ही पूरा होगा। गत 3 जुलाई को तिरुवनंतपुरम में श्री शाह ने कहा कि केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाए बगैर भाजपा का मिशन पूरा नहीं होगा।

केरल में पार्टी की स्थिति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि भाजपा राज्य में सत्तारूढ माकपा द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा के बावजूद सही दिशा में क्रमिक रूप से बढ़ रही है। उन्होंने राज्य में पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2019 के लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटें दिलाने के लिए अथक परिश्रम करने को कहा।

श्री शाह ने कहा कि भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ताओं का बलिदान तब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक कि माकपा को केरल और पश्चिम बंगाल से उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पी. विजयन राज्य में राजनीतिक हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। श्री शाह ने कहा कि विजयन के गृह नगर कन्नूर में भाजपा-आरएसएस के 84 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राजग ने भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार दी है।

इससे पहले दिन में श्री शाह ने पार्टी की प्रदेश इकाई की कोर कमेटी की एक बैठक को भी संबोधित किया। श्री शाह ने केरल के मुख्यमंत्री के इस आरोप को खारिज कर दिया कि केंद्र राजनीतिक आधार पर उसे नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने विकास कार्यक्रमों को लागू करने में बाधाएं पैदा करने के लिए माकपा नीत एलडीएफ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाई क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए जरूरी जमीन नहीं सौंपी।

श्री शाह ने कहा कि चाहे यह एम्स हो, कोझीकोड रेल कोच फैक्टरी हो, या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हो... तीन साल पहले इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने जमीन नहीं आवंटित की। श्री शाह ने विजयन के उस हालिया आरोप का जिक्र करते हुए यह कहा, जिसके तहत केरल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार केरल और इसकी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ■

भुवनेश्वर (ओडिशा)

'प्रदेश में परिवर्तन करने का मन बना चुकी है जनता'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 जुलाई को अपने एकदिवसीय ओडिशा दौरे के दौरान पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से केंद्र में मोदी सरकार के चार साल के दौरान शुरू की गई विभिन्न जनहित योजनाओं को आंदोलन के तौर पर जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए जमीन स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आज राज्य की जनता में ओडिशा सरकार के प्रति आक्रोश भरा पड़ा है। गांव में अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं मिलती। ऐसे में उन्होंने राज्य के लोगों के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान किया है। श्री शाह ने कहा कि ओडिशा में 2019 में परिवर्तन करने का मन जनता बना चुकी है। जनता की इसी भावना को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए अपने संगठन को मजबूती देने में जी जान लगा देने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर फसल बीमा योजना जैसी तमाम योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए जुटने का आह्वान किया। इसके साथ पार्टी मोर्चाओं को और शक्तिशाली बनाने का आह्वान दिया।

इस बैठक में कटक, पुरी एवं भुवनेश्वर लोकसभा के 21 विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत से दो दो लोगों को बुलाया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्वश्री जुएल ओराम एवं धर्मेन्द्र प्रधान, ओडिशा प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) सौदान सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बसंत पंडा सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ■

जीएसटी सहकारी संघवाद का आदर्श उदाहरण

अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या 70 प्रतिशत बढ़ी

एक जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू हुए एक वर्ष हो गए। जीएसटी लागू होने के एक साल के भीतर ही अप्रत्यक्ष करदाताओं का आधार 70 प्रतिशत बढ़ गया। इसके लागू होने से चेक-पोस्ट समाप्त हो गये। ई-वे (इलेक्ट्रॉनिक वे) प्रणाली को लागू किए जाने से देशभर में वस्तुओं की बाधामुक्त आवाजाही सुनिश्चित हुई। 'एक राष्ट्र-एक कर' का सपना साकार हुआ। व्यापार करने में सुगमता आई। जीएसटी से 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिला। इसके तहत कई प्रकार के करों को समावेशित किए जाने से अप्रत्यक्ष करों की एक समन्वित प्रणाली ने भारत को एक आर्थिक संघ बनाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। सच तो यह है कि जीएसटी सहकारी संघवाद का आदर्श उदाहरण है।

जीएसटी को लागू किए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था में रूपांतरकारी परिवर्तन आया। जीएसटी से बहु-स्तरीय, जटिल अप्रत्यक्ष कर संरचना की जगह एक सरल, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी आधारित कर व्यवस्था अस्तित्व में आई। यह व्यवस्था अंतःराज्य व्यापार एवं वाणिज्य की बाधाओं को समाप्त कर भारत को एकल, एकसमान बाजार में बदल दिया।

निर्यातकों, छोटे व्यापारियों एवं उद्यमियों, कृषि एवं उद्योग, आम उपभोक्ताओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों को होने वाले लाभ की वजह से जीएसटी का अर्थव्यवस्था पर कई प्रकार से सकारात्मक प्रभाव पड़ा। यही नहीं, सरकार ने जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए एक आईटी समस्या समाधान तंत्र विकसित किया।

मर्सिडीज, दूध पर नहीं लग सकता एक ही दर से कर: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने की अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता।

श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने की कांग्रेस पार्टी की मांग को यदि स्वीकार किया जाता है तो इससे खाद्यान्न और कई जरूरी वस्तुओं पर कर बढ़ जायेगा।

श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी समय के साथ बेहतर होने वाली प्रणाली है। इसे राज्य सरकारों, व्यापार जगत के लोगों और संबंध पक्षों से मिली जानकारी और अनुभवों के आधार इसमें लगातार सुधार किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''यह काफी आसान होता कि जीएसटी में केवल एक ही दर रहती, लेकिन इसका यह भी मतलब होगा कि खाद्य वस्तुओं पर कर की दर शून्य नहीं होगी। क्या हम दूध और मर्सिडीज पर एक ही दर से कर लगा सकते हैं?''

उन्होंने कहा, ''इसलिये कांग्रेस के हमारे मित्र जब यह कहते हैं कि हमारे पास जीएसटी की केवल एक दर होनी चाहिये, उनके कहने का मतलब है कि वह खाद्य पदार्थों और दूसरी उपभोक्ता जिंसों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगाना चाहते हैं। जबकि वर्तमान में इन उत्पादों पर शून्य अथवा पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया जा रहा है।''

श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जहां 66 लाख अप्रत्यक्ष करदाता ही पंजीकृत थे, वहीं एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद इन करदाताओं की संख्या में 48 लाख नये उद्यमियों का पंजीकरण हुआ है। ■

जून 2018 के महीने में 95,610 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रह

जून 2018 के महीने में 95,610 करोड़ रुपये का कुल सकल राजस्व संग्रह किया गया जिसमें से सीजीएसटी 15,968 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 22,021 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 49,498 करोड़ रुपये (आयातों पर संग्रहित 24,493 करोड़ रुपये सहित) एवं 8,122 करोड़ रुपये (आयातों पर संग्रहित 773 करोड़ रुपये सहित) हैं।

जून महीने में निपटान के बाद केंद्र सरकारों एवं राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 31,645 करोड़ रुपये एवं एसजीएसटी के लिए 36,683 करोड़ रुपये है। वर्तमान महीने में 95,610 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया गया, जबकि पिछले महीने के दौरान यह राजस्व राशि 94,016 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त, जून 2018 के महीने में 95,610 करोड़ रुपये का कुल सकल राजस्व संग्रह किया गया, जबकि पिछले वित वर्षों में जीएसटी संग्रह का मासिक औसत 89,885 करोड़ रुपये था।

जून, 2018 के महीने में, अतिरिक्त अस्थायी निपटान किया गया है और केंद्र एवं राज्यों के बीच 50,000 करोड़ रुपये का निपटारा किया गया है। कथित अस्थायी निपटान फरवरी, 2018 में किए गए 35,000 करोड़ रुपये के पहले के अस्थायी निपटान के अतिरिक्त किया गया है।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 11.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने 1 जुलाई को प्रथम जीएसटी दिवस मनाया। जीएसटी की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली ने सीधा (लाइव) वीडियो लिंक के जरिये गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया। केन्द्रीय रेल, कोयला, वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वित्त राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे।

वीडियो लिंक के जरिये गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए श्री अरुण जेटली ने जीएसटी पूर्व कर प्रणाली का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि भारत में जीएसटी से पहले जो कर प्रणाली थी, वह दुनिया की सर्वाधिक जटिल कर प्रणालियों में से एक थी। तरह-तरह के करों, करदाताओं द्वारा कई तरह के रिटर्न भरने, अनगिनत कर अधिकारियों से सामना होना, टैक्स पर टैक्स लगाये जाने, बढ़ती महंगाई, देश भर में वस्तुओं की कोई मुक्त आवाजाही न होने, देश भर में बाजारों का विखंडित होने जैसे विभिन्न मसलों से भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली समस्याग्रस्त थी। श्री जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने लोगों को कर चोरी किए बगैर ही पारदर्शी ढंग से कारोबार करने के लिए प्रेरित किया।

श्री जेटली ने कहा कि जीएसटी को भारत के प्रधानमंत्री की ओर से सुस्पष्ट समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे केन्द्र सरकार के लिए यह संभव हो पाया कि वह राज्यों से प्राप्त पूर्ण सहयोग के साथ जीएसटी को अत्यंत सफल बना सके। मंत्री महोदय ने कहा, 'हमने इन कारणों का विश्लेषण किया कि आखिरकार पिछली सरकारें जीएसटी को लागू क्यों नहीं कर पाईं। हमने राज्यों द्वारा उठाये गये समस्त मसलों को सुलझाया और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि उनके राजस्व संग्रह में कमी होने की भरपाई निश्चित तौर पर की जाएगी। जीएसटी परिषद भारत की प्रथम आम सहमति आधारित संघीय निर्णय निर्माता संस्था है।'

एक साल की छोटी सी अवधि में जीएसटी द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय सफलताओं का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि इस अभूतपूर्व सुधार ने एक एकीकृत बाजार का सृजन किया है, टैक्स पर टैक्स लगाये जाने की समस्या को समाप्त किया है, कुल कराधान बास्केट का भारांक औसत कम हो गया है, जीएसटी परिषद टैक्स स्लैबों को तर्कसंगत बनाने पर निरंतर काम कर रही है, जीएसटी के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष करों का अग्रिम भुगतान बढ़ गया है, इत्यादि।

मंत्री महोदय ने यह जानकारी दी थी कि जीएसटी को लागू किये जाने के बाद पिछले वित्त वर्ष के नौ माह की अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष करों का कुल संग्रह लगभग 8.2 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो समूचे वर्ष के आधार पर लगभग 11 लाख करोड़ रुपये बैठता है। इस तरह प्रत्यक्ष करों के संग्रह में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जीएसटी के वर्तमान स्लैबों को तर्कसंगत बनाने की गुंजाइश का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद इस दिशा में निरंतर काम कर रही है और जीएसटी प्रणाली में स्थिरता आने, कर चोरी की रोकथाम के जरिये कर संग्रह बढ़ने और कर दायरा बढ़ने से इन स्लैबों को अपेक्षित ढंग से तर्कसंगत बनाना संभव हो जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि उनके अनुमान के अनुसार गैर-तेल श्रेणी में अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है, जिससे निकट भविष्य में टैक्स स्लैब स्वतः ढंग से ही तर्कसंगत हो जाएंगे।

श्री जेटली ने अपने संबोधन के समापन में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना आज जीएसटी इस तरह से अत्यंत सफल नहीं हो पाता। मंत्री महोदय ने कहा कि वैसे तो जीएसटी की प्रथम वर्ष की उपलब्धियों पर प्रसन्न होने के कई कारण हैं, लेकिन समाज में इसके बहुमूल्य योगदान के रूप में जीएसटी का सर्वोत्तम नतीजा आना अभी बाकी है।

इस अवसर पर केन्द्रीय रेल, कोयला, वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जीएसटी को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले राज्यों के नेतृत्व सहित समस्त हितधारकों को बधाई दी, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दल, अधिकारीगण और व्यापार एवं उद्योग जगत भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी सहकारी एवं सहयोगात्मक संघवाद का एक प्रतीक है और जीएसटी दिवस 1.25 अरब भारतीयों का विशेष दिवस है। अतः इसका जश्न मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जीएसटी की उल्लेखनीय सफलता के लिए एक-दूसरे को बधाई देनी चाहिए।

इस अभूतपूर्व कर सुधार का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने एक संविधान के जरिये पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था, सरदार पटेल ने भौगोलिक दृष्टि से विखंडित राष्ट्र को एकजुट किया था और अब जीएसटी एक ऐसा उल्लेखनीय सुधार साबित हुआ है जिसने 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' के सिद्धांत के जरिये पूरे राष्ट्र को एक आर्थिक संघ में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में इतना विशाल ऐसा कोई भी देश नहीं है, जो इतने अधिक क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक हितों के

बावजूद इतिहास में इतने व्यापक कर सुधार को सफलतापूर्वक लागू कर पाया है।

श्री गोयल ने कहा कि इस सुधार ने कर प्रशासन को सरल बना कर और अप्रत्यक्ष करों के ईमानदारीपूर्वक भुगतान के जरिये देश के व्यापार एवं उद्योग जगत की संस्कृति में व्यापक बदलाव लाकर टैक्स की चोरी जैसी अवैध गतिविधियों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ इस कर सुधार को अपनाया है। श्री गोयल ने कहा कि यह कर सुधार भारत की युवा पीढ़ी को समर्पित है, जो अपने कारोबार का संचालन वैधानिक और पारदर्शी ढंग से करना चाहती है।

श्री गोयल ने जीएसटी को छोटे कारोबारियों के लिए 'गेम चेंजर' बताते हुए कहा कि 20 लाख रुपये तक के कारोबार (टर्नओवर) वाले उद्यमों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है और एक करोड़

रुपये तक के कारोबार वाले उद्यमों को 1 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में एक संशोधन के जरिये इस सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार को इसके दायरे में लाने का मन बनाया गया है।

जीएसटी के तहत टैक्स स्लैबों में कमी का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने यह स्पष्ट किया कि भारत के सामाजिक-आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए जीएसटी परिषद में व्यापक विचार-विमर्श के बाद टैक्स के विभिन्न स्लैब तय किये गये हैं। मंत्री महोदय ने देश के नागरिकों को कर चोरी की प्रवृत्ति समाप्त करने में मदद करने और जीएसटी की सफलता तथा इस देश के विकास में पूरे उत्साह के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि 01 जुलाई, 2017 की मध्य रात्रि से जीएसटी को लागू किया जाना संभवतः भारत की आजादी के बाद ऐसा दूसरा ऐतिहासिक अवसर है, जिस दौरान सांसदों ने मध्य रात्रि में सदन में बैठकर देश में ऐतिहासिक बदलाव सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के ऐतिहासिक निर्णयों में शुरुआत में आने वाली अनेक कठिनाइयों के बावजूद आम आदमी अब जीएसटी को अच्छी तरह से समझ गया है और इसके साथ ही वह जीएसटी के कार्यान्वयन में पूरी ईमानदारी के साथ योगदान कर रहा है।

वित्त सचिव डॉ. हसमुख अधिया ने 'प्रथम जीएसटी दिवस' को सहकारी संघवाद की भावना के साथ जश्न मनाने का दिवस बताया, जो जीएसटी की सफल यात्रा में जीएसटी परिषद के कामकाज में स्पष्ट रूप से नजर आती है। उन्होंने कहा कि इस कर सुधार से महंगाई और राजस्व संग्रह पर कुछ भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है और एक साल की छोटी सी अवधि में ही जीएसटी में स्थिरता आ गई है।

डॉ. अधिया ने विभिन्न आंकड़ों के जरिये अपनी दलील को सही बताते हुए कहा कि पिछले नौ महीनों के दौरान हर माह औसतन 89,885 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर का संग्रह हुआ है। इसके अलावा अप्रैल में 1.03 लाख करोड़ रुपये, मई में 94,016 करोड़ रुपये और जून में 95,610 करोड़ रुपये के कर संग्रह से यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी में स्थायित्व आ गया है। अपने संबोधन के समापन में डॉ. अधिया ने फर्जी बिलों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने और जीएसटी को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए व्यापार एवं उद्योग जगत से व्यापक सहयोग करने को कहा। सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एस.रमेश ने जीएसटी को लागू किये जाने के बाद पिछले वर्ष को एक उल्लेखनीय वर्ष बताया।

इस अवसर पर उद्योग जगत की अनेक हस्तियां उपस्थित थीं, जिनमें सीआईआई के अध्यक्ष श्री राकेश भारती मित्तल, फिक्की के अध्यक्ष श्री आर.शाह, एसोचैम के अध्यक्ष श्री संदीप जजोदिया, पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के श्री अनिल खेतान और भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के संघ के अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र त्रिपाठी शामिल हैं।

इन सभी ने भारत के इतिहास में सबसे बड़े कर सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने वास्तव में भारत में कारोबार करने के तौर-तरीकों में बदलाव ला दिया है। इस अवसर पर श्री गोयल और श्री शुक्ला ने जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 35 अधिकारियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये।

इस अवसर पर जो अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, उनमें वित्त मंत्रालय में सचिव श्री महेन्द्र सिंह, जीएसटी परिषद के सदस्य, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सीबीडीटी के अध्यक्ष, जीएसटीएन के अध्यक्ष, सीबीआईसी के पूर्व अध्यक्ष और मंत्रालय एवं सीबीआईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा उद्योग चैम्बरों के सदस्यगण भी शामिल हैं। ■

विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही मानव मूल्यों की रक्षा संभव

दीनदयाल उपाध्याय

भारतीय जनसंघ के पास एक स्पष्ट आर्थिक कार्यक्रम है। किंतु उसका स्थान हमारे संपूर्ण कार्यक्रम में उतना ही है, जितना भारतीय संस्कृति में 'अर्थ' का है। पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवादी होने के कारण अर्थप्रधान है। हम भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद दोनों का समन्वय करके चलना चाहते हैं। अतः यह निश्चित है कि जनसंघ उन अर्थशास्त्रियों एवं दलों से, जो 'अर्थ' के सामने जीवन के प्रत्येक मूल्य की उपेक्षा करके चलाना चाहते हैं, इस मामले में सदैव पीछे रहेगा। जनसंघ हृदय, मस्तिष्क और शरीर तीनों का सम्मिलित विचार करता है। इसी कारण कुछ लोग जनसंघ पर यह आरोप भी लगाते हैं कि जनसंघ आध्यात्मिकता की उपेक्षा करता है। महर्षि अरविंद आदि आध्यात्मिक महापुरुषों की भाषा नहीं बोल पाता है। इन दोनों प्रकार के आरोपों का स्वागत करते हैं और इतना ही कहना चाहते हैं कि जो अर्थ समाज की धारणा के लिए आवश्यक है, जितने मात्र से व्यक्ति अपना भरण-पोषण करके अन्य श्रेष्ठ मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकें, उतने को ही हमने अपने कार्यक्रम में स्थान दिया है।

यह संघर्ष सही नहीं है

आज विश्व में दो गुटों का संघर्ष चल रहा है। एक ओर अमरीका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश हैं, तो दूसरी ओर रूस के नेतृत्व में समाजवादी अथवा साम्यवादी गुट। यद्यपि हमारी विदेशी नीति तटस्थ है, पर वैचारिक दृष्टि से हमें उनमें से एक गुट अर्थात् समाजवादी गुट में सम्मिलित होने के लिए तैयार किया जा रहा है। जनसंघ चाहता है कि विदेश नीति के समान ही हमें वैचारिक क्षेत्र में भी तटस्थ रहना चाहिए। जो लोग पश्चिमी विचारधारा में पले हैं और उन विचारधाराओं में प्रयुक्त शब्दावली के आधार पर ही दुनिया की सब चीजों को समझ सकते हैं, उनका कहना है कि भारत में भी पूंजीवाद और समाजवाद का संघर्ष चल रहा है। वास्तव में यह विश्व के वैचारिक संघर्ष की प्रतिछाया मात्र है, उसका अस्तित्व हमारे यहां है नहीं। हमारा कहना है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के संघर्ष की चर्चा यहां उठाना निरर्थक और निराधार है। हमें उससे ऊपर उठकर समस्याओं की ओर देखना चाहिए।

मनुष्य व्यवस्था से पहले

यदि हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो दिखाई पड़ेगा कि दोनों के दोषों का मूल कारण एक है। उनकी जड़ें अलग-अलग नहीं हैं। अतः हम यह खोजें कि बुराई कहां है? बुराई का वास्तविक कारण व्यवस्था नहीं, मनुष्य है। मनुष्य ही प्रथम आता है। बुरा व्यक्ति अच्छी से अच्छी व्यवस्था में घुसकर बुराई फैला देगा। समाज की प्रत्येक परंपरा और व्यवस्था किसी-न-किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा प्रारंभ की गई। परंतु उसी अच्छी परंपरा पर जब बुरा व्यक्ति आ बैठा, तो वहां बुराई आ गई। राज्य संस्था को ही लें। क्या रामचंद्रजी राजा नहीं थे? जहां उन्होंने अपने श्रेष्ठ जीवन से राज्य संस्था के गौरव में वृद्धि की तो अनेकों ने अपने दोषों से उसी को इतना अपवित्र कर दिया कि कई बार राज्य संस्था का नाम लेने भर से ही चिढ़ उत्पन्न होती है। इसी दृष्टि से निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संघर्ष की ओर देखें। इसकी क्या गारंटी है कि यदि कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र में स्वतंत्र रहकर बुराई करता है, तो उसके स्थान पर राज्य का व्यक्ति बैठा देने पर बुराई न फैलेगी? अतः हमारा ध्यान व्यक्ति की कर्तव्य भावना को जगाने पर केंद्रित होना चाहिए था।

आर्थिक मनुष्य की भ्रामक कल्पना

परंतु हुआ क्या? व्यक्ति की ओर दुर्लक्ष्य और बाह्य व्यवस्था पर जोर दिया गया। निर्जीव व्यवस्था के सामने चेतन मनुष्य नगण्य माना गया। व्यक्ति के अंदर विद्यमान सद्गुणों के विकास करने के स्थान पर उनका ह्रास करनेवाले उपायों का ही अवलंबन किया गया। राष्ट्र निर्माण की योजनाएं बनानेवालों ने इस तथ्य को सर्वथा भुला दिया कि प्रयास करने पर मनुष्य मानव से देवता बन सकता है। उन्होंने मानव का गर्हित स्वरूप। ही सामने लाकर रखा। वे पूंजीवाद के आधार में एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करके चलते हैं, जो विशुद्ध आर्थिक मनुष्य है। यह केवल एक कल्पना है। ऐसा कोई व्यक्ति न कभी पैदा हुआ है और न

होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मनुष्य का चाहे वह पूंजीपति हो या मज़दूर, प्रत्येक कार्य अर्थ की दृष्टि से होता हो। वह अर्थ का विचार भले ही करता होगा, पर उसके कार्य की प्रेरणा अर्थ ही नहीं हो सकती। अर्थशास्त्र के नियमों की कसौटी पर यदि मानवी व्यवहार को कसा जाए तो आपको कहीं भी आर्थिक मनुष्य के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि उससे कहीं विशाल संपूर्ण मानव का अस्तित्व दिखाई देगा।

पूंजीवाद का आधार यदि आर्थिक मनुष्य माना गया तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप समाजवाद ने सामूहिक मनुष्य की कल्पना की। मनुष्य को एक प्रकार मान लिया। उस सामूहिक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का लक्ष्य ही सामने रखा। उसके जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूरी उपेक्षा कर दी। इन दोनों व्यवस्थाओं में मनुष्यता का विचार नहीं है।

मनुष्य पुर्जा बन गया

मनुष्यता की व्याख्या कठिन है। अनेक बातें समान होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ विशिष्टता है। उसकी विविधताओं का विचार आवश्यक है। भारतीय संस्कृति ने एक विचार किया कि मनुष्य इन विविधताओं का स्वाभाविक विकास करते हुए भी आंतरिक एकात्मता की अनुभूति करता चले। व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वप्रथम है। जब टाटा-बिड़ला व्यक्ति स्वातंत्र्य या मुक्त प्रेरणा की बात करते हैं, तो उसका अभिप्राय होता है उनकी अपनी स्वतंत्रता, उनके कारख़ानों में गुलाम बने हुए लाखों-करोड़ों मज़दूरों की स्वतंत्रता नहीं। हमें तो लाखों-करोड़ों मानवों की स्वतंत्रता का विचार करना है। शक्ति, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक, केंद्रीकरण से व्यक्ति-स्वातंत्र्य समाप्त हो जाता है। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों केंद्रीकरण के हामी हैं। पूंजीवाद में धीरे-धीरे मुक्त प्रतियोगिता समाप्त होकर आर्थिक शक्ति पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। अमरीका आदि पूंजीवादी देशों में जो बड़े-बड़े औद्योगिक साम्राज्य बसे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है? आज जितने न्यास विरोधी क़ानून (Anti Trust Laws) अमरीका में बनाने पड़े हैं, उतने कहीं भी नहीं हैं। वहां व्यवहार व्यक्तियों के साथ नहीं, फ़ाइलों के साथ होता है। आर्थिक शक्ति को राज्य के हाथों में सौंपनेवाले समाजवाद में भी ऐसा ही होता है। राज्य की नौकरशाही भी यही करती है। परिणाम हो रहा है कि जीवन यंत्रवत् होता जा रहा है। मनुष्यों का स्थान फ़ाइलें ले रही हैं। मानवता समाप्त होती जाती है। दोनों व्यवस्थाओं में मनुष्य का विचार होता है तो परिमाणात्मक आधार पर, न कि गुणात्मक आधार पर।

मानववाद चाहिए

जब तक एक-एक व्यक्ति की विशिष्टता-विविधता को ध्यान में रखकर उसके विकास की चिंता नहीं करेंगे, तब तक मानवता की सच्ची सेवा नहीं होगी। समाजवाद और पूंजीवाद ने मनुष्य को व्यवस्था के निर्जीव यंत्र का एक पुर्जा मात्र बना डाला। एक स्वतंत्र जुलाहे को समाप्त कर उसे विशाल कारख़ाने का मज़दूर बना दिया गया। बजाज (किराने की दुकान) के स्थान पर एक विभागीय स्टोर्स बना दिया गया। दर्जी के स्थान पर रेडीमेड कपड़ा लाकर रख दिया। मनुष्य यानी एक जंतु जो आठ घंटे यंत्रवत् मजूरी करे और सोलह घंटे खाए। कार्य और जीवन के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। पश्चिम के कई देशों में कहा जाता है कि पांच दिन काम के और दो दिन छुट्टी के। उन दो दिनों में केवल मस्ती, केवल खाना-पीना और मौज, काम की बात भी नहीं। अर्थात् वे पांच दिन कमाई करते हैं और दो दिन जीवित रहते हैं। अतः हमें मनुष्य-मनुष्य के कमाई के साधनों का इस प्रकार निर्धारण करना होगा कि उसके कार्य और वास्तविक जीवन के बीच कोई खाई न रहे। हाड़-मांस के मनुष्य, जिसके पास हृदय, मस्तिष्क और शरीर तीनों की भूख है, का ही विचार करना होगा। अन्यथा कार्य के आठ घंटों का जो अमानवी प्रभाव होता है, उसे समाप्त करने में ही उसके शेष सोलह घंटे व्यतीत हो जाते हैं। उनके समाप्त होते ही वह पुनः उन आठ घंटों के चक्र में फंस जाता है।

मनुष्यता की व्याख्या कठिन है। अनेक बातें समान होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ विशिष्टता है। उसकी विविधताओं का विचार आवश्यक है। भारतीय संस्कृति ने एक विचार किया कि मनुष्य इन विविधताओं का स्वाभाविक विकास करते हुए भी आंतरिक एकात्मता की अनुभूति करता चले।

विज्ञान और मानवता

अतः इन पूंजीवाद और समाजवाद के चक्कर से मुक्त होकर मानववाद का विचार करें। मानव जीवन के समस्त पहलुओं का विचार कर आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, वितरण और उपभोग के साधन तथा व्यवस्था बनाएं। फिर उसके लिए विज्ञान का उपयोग करें। यह आवश्यक नहीं कि हम विज्ञान के पुराने प्रयोगों को ज्यों-का-त्यों अपना लें। आज हम पश्चिम की तकनीक की आंख मूंदकर नक़ल कर रहे हैं। इसे बंद करना होगा और तकनीक का प्रयोग मानवता के विकास के लिए करना होगा।

विकेंद्रित अर्थव्यवस्था

इसके लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहिए। स्वयंसेवी क्षेत्र को खड़ा करना होगा। यह क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उतना ही मनुष्य आगे बढ़ सकेगा, मनुष्यता का विकास हो सकेगा. एक मनुष्य दसरे मनुष्य का विचार कर सकेगा। प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिशः आवश्यकताओं और

विशेषताओं का विचार करके उसे काम देने पर उसके गुणों का विकास हो सकता है। यह विकेंद्रित अर्थव्यवस्था भारत ही संसार को दे सकता है। हम नए सिरे से आर्थिक निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। अतः हमें यह विकेंद्रित अर्थव्यवस्था खड़ी करने में सुविधा हो सकती है, जबकि दुनिया शायद यह बात आसानी से न कर पाए। क्योंकि यदि एक बार बड़े भारी कारख़ाने का निर्माण हो गया, तो उसे समाप्त करने की बात सोचने से अनेकों व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। उसके लिए बड़ा साहस बटोरना पड़ता है, भारी उथल-पुथल के लिए तैयार होना पड़ता है। अतः राष्ट्र निर्माण की इस प्रारंभिक वेला में हम अपना पग आगे बढ़ाते समय अच्छी प्रकार विचार करें।

यदि इसी चीज़ को खेती के क्षेत्र में लाकर देखें, तो सहकारी खेती का अंतिम चित्र होगा ग्राम व्यवस्था, उसमें किसान का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अभी मैं उत्पादन के प्रश्न को नहीं उठाता। वह दूसरे नंबर पर है। प्रथम बात तो यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाने के कारण सुख के स्थान पर दुःख आता चला जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता समाप्त हुई तो राजनीतिक क्षेत्र में भी समाप्त हो जाती है। समाजवाद और प्रजातंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते। सच्चे प्रजातंत्र का आधार आर्थिक विकेंद्रीकरण ही हो सकता है। अतः सिद्धांततः हमें छोटे-छोटे उद्योगों को ही अपनाना चाहिए।

बेकारी का प्रश्न

अब व्यावहारिक दृष्टि से देखें। हमारी योजनाएं श्रम प्रधान होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। आज की योजनाओं की सबसे बड़ी ख़राबी यह है कि उनमें देश की स्थिति और आवश्यकताओं का विचार नहीं किया गया। पश्चिम हमें बड़ी-बड़ी मशीनें दे रहा है, हम लेते जा रहे हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था लाई जा रही है, जिसके कारण देश की बेकारी बढ़ती जा रही है। यदि बेकारी कम होने के स्थान पर बढ़ती ही गई तो देश की प्रगति का आधार क्या? यह मैं मान सकता हूं कि बेकारी एकदम दूर नहीं हो सकती, पर योजनाएं बनाने से पहले हमें प्रत्येक व्यक्ति को काम के सिद्धांत को मान्यता देनी पड़ेगी। यदि इसे मान लिया तो योजनाओं की दिशा एवं स्वरूप बदल जाएगा, भले ही बेकारी धीरे-धीरे दूर हो।

राष्ट्रीय आय

आजकल राष्ट्रीय आय का विचार औसत के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, पर यह बहुत बड़ा भ्रम है। राष्ट्रीय आय बढ़ती जाने के बाद भी देश की ग़रीबी बढ़ती जा रही है। यह क्यों? राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़े। प्रत्येक को काम दिया तो ग़रीबी घटेगी, प्रत्येक की आय में वृद्धि होगी। इससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। यह सत्य है कि कम मनुष्यों का उपयोग करनेवाली बड़ी मशीनों के द्वारा भी उत्पादन बढ़ सकता है, पर वह हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं। गांधीजी कहा करते थे, मैं विशाल उत्पादन चाहता हूं, परंतु विशाल जनसमूह के द्वारा उत्पादन चाहता हूं।

उत्पादन का सही ढंग

अब बड़ी मशीनों के आधार पर जो उत्पादन बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, उससे देश में बेकारी तो बढ़ ही रही है, विदेशी ऋण भी बढ़ता जा रहा है। आज हमारे राष्ट्र की पूरी आय का 55 प्रतिशत हम पर ऋण है। बढ़ते हुए विदेशी ऋण के कारण विदेशी मुद्रा विनियम की समस्या खड़ी हो गई है। अतः उसके कारण हमारा नारा उत्पादन करो या मर जाओ' के स्थान पर निर्यात करो या मर जाओ' हो गया है। हमारी भावी योजनाएं निर्यात पर आधारित होने के कारण जो चीज हम पैदा करते हैं, उसका भी उपभोग नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ, चीनी का हम स्वयंपूर्ण बाज़ार खड़ा कर सकते थे, पर हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए चीनी सस्ते मूल्य पर विदेशों में बेचनी पड़ती है। अतः देश में महंगे मूल्य पर बेची जा रही है। अपनी गाय-भैंसों को खली और भूसा न खिलाकर हम विदेशों को भेज रहे हैं और दूध के डिब्बों का आयात कर रहे हैं। वेजिटेबल घी बनानेवाली मशीनों को मंगाते हैं।

जब तक एक-एक व्यक्ति की विशिष्टता-विविधता को ध्यान में रखकर उसके विकास की चिंता नहीं करेंगे, तब तक मानवता की सच्ची सेवा नहीं होगी। समाजवाद और पूंजीवाद ने मनुष्य को व्यवस्था के निर्जीव यंत्र का एक पुर्जा मात्र बना डाला। एक स्वतंत्र जुलाहे को समाप्त कर उसे विशाल कारख़ाने का मज़दूर बना दिया गया।

आज हम देश की प्रगति का हिसाब मशीनों में लगाते हैं। एक सज्जन ने अमरीका की तुलना में भारत के पिछड़ेपन का उल्लेख करते हुए इस्पात के उपभोग को मानदंड के रूप में प्रस्तुत किया। अतः उन्होंने कहा कि पूरी शक्ति लगाकर अमरीका के बराबर पहुंचना चाहिए, पर वे यह भूल गए कि अब तो प्लास्टिक का युग प्रारंभ हो गया है। अगर पांच-दस साल में हम इस्पात के उत्पादन में अमरीका के बराबर पहुंच भी गए तो आर्थिक प्रगति का मापदंड प्लास्टिक का उपभोग हो जाएगा और हम पुनः पिछड़े रह जाएंगे। अतः हम जीवन स्तर का ठीक निश्चय करें।

इसका विचार करके ही हम उत्पादन के साधनों का निश्चय करें। यदि ज्यादा आदमियों का उपयोग करनेवाले छोटे-छोटे कुटीर उद्योग अपनाए गए तो कम पूंजी तथा मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे नौकरशाही का बोझ कम होगा, विदेशी ऋण को भी नहीं लेना पड़ेगा। देश की सच्ची प्रगति होगी तथा प्रजातंत्र की नींव पक्की हो जाएगी। ■

(-पाञ्चजन्य, मार्च 30, 1959 से साभार)

बाल गंगाधर तिलक

(23 जुलाई 1856– 1 अगस्त, 1920)

बाल गंगाधर तिलक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और प्रखर राष्ट्रवादी थे इन्होंने 'इंडियन होमरूल लीग' की स्थापना सन् 1914 ई. में की और इसके अध्यक्ष रहे।

जीवन परिचय

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, सन् 1856 ई. को भारत के रत्नागिरि नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम 'लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक' था। इन्होंने सन् 1876 ई. में बी.ए. ऑनर्स की परीक्षा पास की और सन् 1879 ई. में बंबई विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. किया। इसके बाद तिलक ने अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया।

स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी

तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे- मोटे सुधार नहीं और उन्होंने कांग्रेस को अपने प्रखर विचारों को स्वीकार करने के लिए राज़ी करने का प्रयास किया। इस मामले पर सन् 1907 ई. में कांग्रेस के 'सूरत अधिवेशन' में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फ़ैलाने का आरोप लगाकर उन्हें छह वर्ष के कारावास की सज़ा दे दी और मांडले, (बर्मा) वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। 'मांडले जेल' में तिलक ने अपनी महान कृति 'भगवद्गीता-रहस्य' का लेखन शुरू किया, जो हिन्दुओं की सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगवद्गीता के इस रूढ़िवादी सार को ख़ारिज कर दिया कि यह पुस्तक संन्यास की शिक्षा देती है; इनके अनुसार, इससे मानवता के प्रति निःस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है।

इंडियन होमरूल लीग की स्थापना

प्रथम विश्वयुद्ध के ठीक पहले सन् 1914 ई. में रिहा होने पर वह पुनः राजनीति में कूद पड़े और 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा' के नारे के साथ इंडियन होमरूल लीग की स्थापना की। सन् 1916 ई. में वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 'इंडियन होमरूल लीग' के अध्यक्ष के रूप में तिलक सन् 1918 में इंग्लैंड गए। गौरतलब है कि तिलक पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा था कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। तिलक सन् 1905 ई. से सक्रिय राजनीतिक आंदोलन में पूरी तरह कूद गए थे। बंगाल के विभाजन के कारण देश में राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्वार आया। इसी के साथ स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि स्वराज्य जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए।

सामाजिक और राजनीतिक दर्शन

अपनी पुरानी परंपरा और संस्थाओं के प्रति जनता में अब नई जागरूकता प्रकट हो रही थी। इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण थे पुरानी धार्मिक आराधना, गणपति-पूजन और शिवाजी के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर महोत्सवों का आयोजन। इन दोनों आंदोलनों के साथ तिलक का नाम घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। तिलक का दृढ़ विश्वास था कि पुराने देवताओं और राष्ट्रीय नेताओं की स्वस्थ वंदना से लोगों में सच्ची राष्ट्रीयता और देशप्रेम की भावना विकसित होगी। विदेशी विचारों और प्रथाओं के अंधानुकरण से नई पीढ़ी में अधार्मिकता पैदा हो रही है और उसका विनाशक प्रभाव भारतीय युवकों के चरित्र पर पड़ रहा है। तिलक का विश्वास था कि अगर स्थिति को इसी प्रकार बिगड़ने दिया गया, तो अंततः नैतिक दिवालिएपन की स्थिति आ जाएगी, जिससे कोई भी राष्ट्र उबर नहीं सकता। तिलक के विचार में भारतीय युवकों को स्वावलंबी और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए उनको अधिक आत्म-सम्मान का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सच तो यह है कि तिलक मौलिक विचारों के व्यक्ति थे। वह संघर्षशील और परिश्रमशील थे। वह विशेष प्रसन्नता का अनुभव तब करते थे, जब उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उनके अधिकांश कार्य परोपकार की भावना से भरे होते थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। उनमें योग्यता, अध्यवसाय, उद्यमशीलता और देशप्रेम का ऐसा अनूठा संगम था कि जिससे अंग्रेज़ सरकार हमेशा चौकस रहती थी। 1 अगस्त, सन् 1920 ई. में बंबई में तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। ■

जीएसटी से जुड़े अनुभव

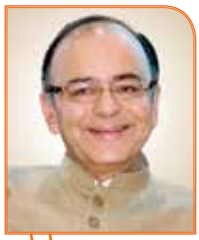

अरुण जेटली

देश में नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)' को लागू किये जाने के बाद एक साल की अवधि पूरी हो चुकी है। इस एकल टैक्स ने उन 17 करों और अनगिनत उपकरों (सेस) का स्थान लिया है, जिसे केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने लागू किया था। इससे पहले देश में अत्यंत जटिल कर प्रणाली लागू थी, क्योंकि प्रत्येक करदाता को तरह-तरह के रिटर्न भरने पड़ते थे, उन्हें कई इंस्पेक्टरों एवं कर निर्धारण अधिकारियों का सामना करना पड़ता था, अपने किसी भी उत्पाद की आवाजाही होने पर प्रत्येक राज्य में अलग से टैक्स अदा करना पड़ता था और तरह-तरह की बाधाओं का सामना करने पर करदाता टैक्स अदायगी से बचने के उपाय ढूंढ़ने लगता था। जीएसटी का आधारभूत विचार मौलिक नहीं था। दुनिया के कई देशों में प्रयोग के तौर पर इसे लागू किया जा चुका है। अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय मॉडल को विकसित करना जरूरी था। भारत राज्यों का एक ऐसा संघ है, जिसमें केन्द्र और राज्यों दोनों को ही राजकोषीय अथवा वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ होना अत्यंत जरूरी है। भारत राज्यों का परिसंघ नहीं है, इसलिए केन्द्र सरकार के राजस्व की कीमत पर राज्यों की राजस्व स्थिति को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता है। यदि केन्द्र का ही अस्तित्व बरकरार नहीं रह पाएगा, तो 'भारत' यानी राज्यों के संघ का क्या होगा?

जीएसटी का दोषपूर्ण यूपीए मॉडल

यूपीए और कांग्रेस पार्टी में मेरे मित्र कभी-कभी इस तरह के सवाल पूछते हैं कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान जीएसटी के विचार से कुछ मुख्यमंत्री सहज क्यों नहीं थे। इसके दो मुख्य कारण थे।

पहला, यूपीए सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों सहित विभिन्न राज्यों का विश्वास खो दिया था। एकल कर प्रणाली को अपनाने की दिशा में कदम उठाते हुए यूपीए ने राज्यों से सीएसटी को समाप्त करने के लिए कहा था। यूपीए ने राज्यों से वादा किया था कि सीएसटी को समाप्त करने के बदले में कुछ वर्षों तक उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। राज्यों ने तदनुसार ऐसा ही किया, लेकिन सीएसटी के बदले में मुआवजा देने का वादा यूपीए ने पूरा नहीं किया। जब मैंने मई, 2014 में वित्त मंत्री का पदभार संभाला, तो भाजपा शासित राज्यों सहित सभी राज्यों ने मुझसे कहा कि यूपीए सरकार ने जैसा किया, उसे देखते हुए वे केन्द्र सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं। राज्यों ने मुझसे कहा कि वे जीएसटी पर चर्चा तभी करेंगे, जब सीएसटी से जुड़ा पिछला मुआवजा उन्हें मिल जाएगा। मैंने तदनुसार वैसा ही किया और सीएसटी मुआवजा अदा कर दिया गया। इसके बाद राज्य जीएसटी पर बात आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गये।

दूसरा कारण यह था कि राज्यों के मन में यह संशय था कि जीएसटी को पूरी तरह से लागू करने के दौरान उन्हें राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह था कि राज्यों को नुकसान की भरपाई किस तरह से की जाएगी। उनकी मांग जायज प्रतीत होती थी, लेकिन यूपीए ने इसका हल नहीं निकाला। विशेषकर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विनिर्माण राज्य इसको लेकर काफी चिंतित थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'मुआवजा नहीं तो जीएसटी नहीं'। जीएसटी परिषद में विचार-विमर्श करने के बाद मैं राज्यों को कुछ भी राजस्व नुकसान होने पर प्रथम पांच वर्षों तक राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि करने पर सहमत हो गया। राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हम इस तरह जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों का भरोसा जीतने में सफल हो गये।

एक साल के बाद अनुभव

जब जीएसटी को 01 जुलाई, 2017 को लागू करना था, तो कांग्रेस ने हमें इसे स्थगित करने की सलाह दी थी। हालांकि, एक अनिच्छुक सरकार कभी भी सुधारवादी निर्णय नहीं ले सकती है। अतः हम इस दिशा में आगे बढ़ गये। पहले चरण में हमने टैक्स दरों का प्रथम सेट तय किया। ऐसे में व्यापार एवं उद्योग जगत से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए और हमने टैक्स दरों को तर्कसंगत करना शुरू कर दिया।

जीएसटी परिषद की आरम्भिक कुछ बैठकों में जहां भी आवश्यक समझा गया उनके मामलों में टैक्स दरों को कम कर दिया गया। जब हम समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर गौर करते हैं, तो हमें प्रतीत होता है कि आज टैक्स दरों की कुल संख्या पिछली कर प्रणाली की तुलना में काफी कम है। टैक्स पर टैक्स लगाये जाने की व्यवस्था समाप्त हो जाने से कर देनदारी कम हो गयी है।

आम सहमति सुनिश्चित करने के लिए हमने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, ताकि सर्वसम्मति से जीएसटी को लागू किया जा सके। जीएसटी से जुड़े सभी विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गये। जीएसटी परिषद के समक्ष संबंधित नियम-कायदे पेश किये गये। उन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। हमने अब तक जीएसटी परिषद की 27 बैठकें की हैं, जिस दौरान प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है।

भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जहां इतने बड़े कर

सुधारों को सुगमतापूर्वक लागू किया गया है। समस्त चेक-पोस्ट को रातों-रात समाप्त कर दिया गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रणाली ने समस्त आवश्यक जानकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर दिया है। जीएसटी ने बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक कर पंजीकरण को प्रोत्साहित किया है। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में की गई विस्तृत गणनाओं से यह पता चला है कि दिसम्बर, 2017 तक लगभग 1.7 मिलियन पंजीकरणकर्ता ऐसे थे, जो जीएसटी सीमा से काफी नीचे आते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जीएसटी का हिस्सा बनने का विकल्प चुना।

बड़े पैमाने पर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ई-वे बिल को पेश किया गया है। जैसे ही इनवॉयस के मिलान का काम शुरू हो जाएगा, तब कर की चोरी अत्यंत कठिन हो जाएगी। करदाताओं को

सुधार की सदा ही गुंजाइश रहती है। भविष्य में उठाये जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों से कर प्रणाली और भी ज्यादा सरल हो जाएगी तथा कर ढांचा तर्कसंगत हो जाएगा। जीएसटी की सबसे बड़ी सफलता यह है कि जीएसटी परिषद एक अत्यंत कारगर एवं प्रभावशाली निर्णय निर्माता संघीय संस्था साबित हुई है।

अब काफी सहूलियत हो गई है। करदाता अब अपने रिटर्न ऑनलाइन भरते हैं और विभिन्न अधिकारियों से उनका सामना अब नहीं होता है। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। कर आधार बढ़ने पर कर की दरों एवं स्लैबों को तर्कसंगत बनाने की हमारी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी।

अत्यंत छोटे कारोबारियों को संरक्षित कर दिया गया है। जिन कारोबारियों का टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है, वे जीएसटी अदा नहीं करते हैं। जिन कारोबारियों का टर्नओवर एक करोड़ रुपये तक है, वे अपने टर्नओवर पर एक प्रतिशत टैक्स की अदायगी के साथ अपने जीएसटी का संयोजन कर सकते हैं और तिमाही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

एकल स्लैब

राहुल गांधी भारत के लिए एकल स्लैब वाले जीएसटी की वकालत करते रहे हैं। यह एक दोषपूर्ण आइडिया है। एकल स्लैब वाला जीएसटी केवल उन्हीं देशों में कारगर साबित हो सकता है, जहां की समूची आबादी एक जैसी है और उनकी अदायगी क्षमता ज्यादा है।

कर का प्रभाव

प्रत्यक्ष कर पर जीएसटी का प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। जिन लोगों को अपने कारोबार के टर्नओवर का खुलासा करना पड़ता है, उन्हें अब आयकर के लिए अपनी आय का खुलासा करना पड़ता है। ऐसे में आरंभिक संकेतों से पता चला है कि प्रत्यक्ष कर का संग्रह बढ़ गया है। जब हम जुलाई, 2017 से लेकर मार्च, 2018 तक के प्रथम नौ महीनों में जीएसटी के प्रदर्शन पर गौर करते हैं और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एवं कम्पोजीशन सेस सहित समस्त संग्रहीत राशि को जोड़ते है, तो हमें जीएसटी संग्रह की पूरी राशि प्राप्त होती है। प्रथम नौ महीनों में 8.2 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि का संग्रह हुआ है, जो वार्षिक आधार पर 11 लाख करोड़ रुपये बैठता है और 11.9 प्रतिशत की वृद्धि अथवा 1.22 की कर उछाल को दर्शाता है, जो ऐतिहासिक रूप से अप्रत्यक्ष करों के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। जीएसटी से मध्यम अवधि में देश का कर आधार मजबूत हो जाएगा, जिससे जीडीपी में 1.5 प्रतिशत की और ज्यादा वृद्धि होगी।

आज मुआवजा उपकर की मदद से राज्य वर्ष 2015-16 के कर आधार में 14 प्रतिशत की वृद्धि हासिल कर रहे हैं। जब रुका हुआ आईजीएसटी केन्द्र और राज्यों को धीरे-धीरे जारी किया जाएगा, तो मुआवजा उपकर के बिना भी ज्यादातर राज्य 14 प्रतिशत के वृद्धि लक्ष्य को पार कर जाएंगे।

अप्रत्यक्ष कर का आधार बढ़ रहा है। देश भर में वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध प्रवाह हो रहा है। 'कारोबार में और ज्यादा सुगमता' सुनिश्चित हो गई है। किसी व्यापक व्यवधान के बिना ही नई कर प्रणाली अपना ली गई है। आरंभिक कठिनाइयों के बाद आईटी प्रणाली अब बेहतर ढंग से काम कर रही है। इन सभी के लिए मैं राजस्व सचिव श्री हसमुख अधिया, सीबीआईसी और केन्द्र एवं सभी राज्यों के राजस्व तथा कर विभागों के समस्त अधिकारियों, जीएसटीएन के पदाधिकारियों और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

सुधार की सदा ही गुंजाइश रहती है। भविष्य में उठाये जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों से कर प्रणाली और भी ज्यादा सरल हो जाएगी तथा कर ढांचा तर्कसंगत हो जाएगा।

जीएसटी की सबसे बड़ी सफलता यह है कि जीएसटी परिषद एक अत्यंत कारगर एवं प्रभावशाली निर्णय निर्माता संघीय संस्था साबित हुई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने संघीय गवर्नेंस के मामले में इतिहास रच दिया है। यह वास्तव में मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इनमें से सभी का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं जीएसटी के रूप में इस ऐतिहासिक बदलाव को मूर्त रूप देने और पूरे राष्ट्र को इस मामले में बेहतरीन अनुभव प्रदान करने में सामूहिक सहयोग देने के लिए वित्त मंत्रियों का धन्यवाद करता हूं। ■

(लेखक केंद्रीय मंत्री हैं)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बढ़ते कदम

थावरचंद गहलोत

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट में 12.19% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में 6908.00 करोड़ रुपये का बजट था, जो बढ़कर वर्ष 2018-19 में 7750.00 करोड़ रुपये हो गया। यह 842.00 करोड़ रुपये की वृद्धि है यानी बजट में 12.19% की वृद्धि हुई है।

धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए 18 राज्यों के 170 चिन्हित जिलों में सिर पर मैला ढोने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है। एनएसकेएफडीसी द्वारा राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से सर्वे का समन्वय और निगरानी किया जा रहा है। 125 जिलों में सर्वेक्षण शिविर पूरा हो चुके हैं और अब तक 5365 लोगों को सिर पर मैला ढोने वाले के रूप में पहचान की गई है।

मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रूप में 25 योजनाएं लागू कर रहा है। 2016-17 और 2017-18 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रमशः 1.45 और 1.66 करोड़ रुपये लाभार्थियों को सहायता/लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रूप में जारी किए गए थे। लाभार्थी डेटाबेस में आधार जुड़ाव 66% तक पहुंच गया है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन में 2015-16 के 30850.88 करोड़ रुपये से वृद्धि करके 56618.50 करोड़ रुपये किया गया। यह 83.52% की वृद्धि है।

अनुसूचित जाति के छात्रों (पीएमएस-एससी) को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में प्रति वर्ष लगभग 60 लाख छात्रों को शामिल किया जाता है। 2014 से 2018 के बीच, 2,29,30,654 छात्रों ने पीएमएस-एससी छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है और 10,388 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए पीएमएस-एससी में 8737 करोड़ रुपये की एकत्रित बकाया राशि को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2018-2019 में इस उद्देश्य के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की दर तथा स्वच्छता के कार्य में शामिल लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 2017-18 से 50 प्रतिशत बढ़ा दी गई है।

अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत अप्रैल, 2014 से मार्च 2018 के बीच 8000 मेधावी छात्रों को 770.80 करोड़ रुपये की फेलोशिप दी गई। 2018-19 में 2000 छात्रों को एमफिल/पीएचडी के लिए फेलोशिप मिलेगी। सभी मेरिट आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने के लिए माता-पिता की आय सीमा को वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर वार्षिक 6 लाख रुपये कर दिया गया है।

अंतरजाति विवाह जिसमें युगल में से एक अनुसूचित जाति का हो, के लिए वर्ष 2017-18 से ढाई लाख रुपये की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत मदद दी जा रही है। इस योजना के तहत जो राशि प्रदान की जाती है, वह संयुक्त खाते में किसी सरकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए सवाधि जमा खाते में रखी जाती है, जोकि तीन वर्ष से पहले नहीं निकाली जा सकती।

केन्द्र सरकार की 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' को अनुसूचित जाति के एकीकृत विकास के लिए मद्देनजर रखते हुए 50 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाले गांवों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत ऐसे 2500 गांवों को कवर किया गया है, जहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है। वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 के लिए 300 करोड़ रुपये का अनुदान 'प्रधानमंत्री

मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्त्र में 25 योजनाएं लागू कर रहा है। 2016-17 और 2017-18 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रमशः 1.45 और 1.66 करोड़ स्पये लाभार्थियों को सहायता/लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्त्र में जारी किए गए थे। लाभार्थी डेटाबेस में आधार जुड़ाव 66% तक पहुंच गया है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन में 2015-16 के 30850.88 करोड़ स्पये से वृद्धि करके 56618.50 करोड़ स्पये किया गया। यह 83.52% की वृद्धि है।

आदर्श ग्राम योजना' के लिए आवंटित किया गया है।

वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए 'वेंचर कैपिटल फंड' की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अब तक अनुसूचित जाति के 71 उद्यमियों को 255 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि में 41.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में जहां इस वर्ग को 1237.30 करोड़ रुपये जारी किये गये थे, वहीं वर्ष 2018-19 में 1747 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अनुसूचित जाति की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 'वेंचर कैपिटल फंड' शुरुआती 200 करोड़ रुपये के कोष के साथ शुरू किया जा रहा है। गैर-क्रीमीलेयर की आय सीमा को 01.09.2017 से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की उपश्रेणियों की जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में 02.10.2017 को आयोग का गठन किया गया, जिसने 11.11.2017 से काम करना शुरू कर दिया।

मद्यपान और मादक पदार्थ से बचाव के लिए योजना के तहत नशा मुक्त केन्द्रों के लिए मंत्रालय ने 01.04.2018 से लागत राशि में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नशा मुक्त केन्द्रों में रसोइया और पूर्णकालिक चिकित्सक के अलावा एक चौकीदार की भी व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना के तहत लागत मानकों को 01.04.2015 को 110 फीसदी बढ़ाया गया था, जिसे आगे 01.04.2018 को फिर से 104 फीसदी बढ़ाया गया। योजना के तहत फिजियोथेरेपिस्ट परिचारक/परिचारिका और योग प्रशिक्षक की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही घरों के पंजीयन, मानकीकरण और रेटिंग के लिए प्रावधान तैयार किए गए हैं। श्री गहलोत ने बताया कि लागत मानदंडों में अंतिम बार संशोधन 01.04.2015 को किया गया था।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत, कुल 292 जिलों का चयन किया गया है, 52 जिलों में मूल्यांकन शिविर और 39 जिलों में वितरण शिविर आयोजित किए जा चुके है, जिनके माध्यम से 43865 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। बीपीएल श्रेणियों के वरिष्ठ नागरिकों को कुल 99431 उपकरण प्रदान किए गए। पहली बार नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले पीड़ितों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में 185 जिलों के 1.5 लाख परिवार और 6 लाख लोगों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण अभी चालू है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) का उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्त बनाना है। इसमें विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजों को सहायता और उपकरण प्रदान करना; भवन, परिवहन और वेबसाइटों के मामले में बाधा मुक्त माहौल तैयार करना; शुरुआती उपाय, स्कूली शिक्षा, एनजीओ के माध्यम से बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण; स्कूलों, कॉलेजों में छात्रवृत्ति, पेशेवर शिक्षा और कौशल विकास के प्रति सहायता प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।

1995 के पुराने कानून को निरस्त कर 2016 में नया कानून लाया गया जिसका नाम 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' है। यह कानून समानता के अधिकार, भेदभाव रहित, सामुदायिक जीवन का अधिकार, न्याय तक पहुंच, शिक्षा, रोजगार इत्यादि की गारंटी देता है। अभी तक 21 प्रकार के दिव्यांगता की पहचान की गई है, जो पहले केवल 7 प्रकार की थीं।

2014 से अभी तक एडीआईपी योजना के तहत 622.45 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जिससे देश भर में 6459 शिविरों के माध्यम से 9.97 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचा। 172 अस्पतालों को कर्णावर्त तंत्रिका प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है और अभी तक 1142 कर्णावर्त तंत्रिका प्रत्यारोपण सर्जरी की जा चुकी हैं। दिव्यांगों के लिए मोटर चालित तिपहिया साइकिल की पात्रता उम्र 18 साल से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। पिछले 4 वर्षों में, 80% से अधिक दिव्यांगजनों को 5693 मोटर चालित तिपहिया साइकिल दी गई। वर्ष 2013-14 में 95.36 करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर 2018-19 के लिए दोगुने से ज्यादा 220 करोड़ कर दिया गया है।

1995 के पुराने कानून को निरस्त कर 2016 में नया कानून लाया गया जिसका नाम 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' है। यह कानून समानता के अधिकार, भेदभाव रहित, सामुदायिक जीवन का अधिकार, न्याय तक पहुंच, शिक्षा, रोजगार इत्यादि की गारंटी देता है। अभी तक 21 प्रकार के दिव्यांगता की पहचान की गई है, जो पहले केवल 7 प्रकार की थीं।

सुगम्य भारत अभियान एक लक्षित कार्यक्रम है और यह सार्वजनिक भवनों, परिवहन, सड़क और वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए राज्य सरकारों को पैसा प्रदान करता है। 1662 इमारतों का ऑडिट किया गया है, 613 भवनों के लिए 160.3 लाख रुपये जारी किए गए हैं। सभी 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुगम्य कर दिया गया है, 48 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया है। 709 ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में से 667 स्टेशनों को सुगम्य बनाया गया है, 13613 बसों को सुगम्य बनाया गया है। राज्यों की 917 वेबसाइटों में से 205 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है। ■

(गत १६ जून को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत विचार पर आधारित)

'एबार, पश्चिम बंगो'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 28 जून को पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से पश्चिम बंगाल में हिंसा एवं भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने आज पुरुलिया में डोर-टू-डोर जनसंपर्क किया और लोगों की समस्याओं से रू-ब-रू हुए। उन्होंने संपर्क अभियान के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर भी जनता के साथ विस्तार से चर्चा की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, ये स्थानीय निकायों के चुनाव थे, यह पश्चिम बंगाल की सत्ता तय करने वाला चुनाव नहीं था, ममता बनर्जी जी की कुर्सी को इससे कोई ख़तरा नहीं था लेकिन इसके बावजूद चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया, कोर्ट के दखल के बाद जब पर्चा भरा गया तो तृणमूल कांग्रेस द्वारा लोगों को धमकाया गया और वोट नहीं डालने दिया। इस सबके बावजूद जब वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई तो हमारे तीन कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि यदि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी यह समझती हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के तांडव से उनकी सरकार बनी रहेगी तो यह उनकी भूल है, हमारे कार्यकर्ताओं का लहू रंग लाएगा और तृणमूल सरकार पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक नहीं चल सकती।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 20 से ज्यादा युवा कार्यकर्ताओं को चुन-चुन कर मारा गया, 1300 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता घायल हुए, कई कार्यकर्ताओं को गलत प्रकार के केस डाले गए और असंख्य कार्यकर्ताओं को भयभीत किया गया। उन्होंने कहा कि कम-से-कम दो करोड़ लोगों को पंचायत चुनाव में वोट नहीं डालने दिया गया लेकिन इस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 6,000 से अधिक सीटों पर विजय मिली और जनता ने भाजपा का झंडा बुलंद किया, यही बताता है कि पश्चिम बंगाल में अगली बार सरकार किसकी चुनकर आने वाली है।

श्री शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव पश्चिम बंगाल में अगली सरकार की नींव डालने वाला है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोक सभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगभग सभी चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अब पश्चिम बंगाल की बारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक नारा दिया है - एबार, पश्चिम बंगो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही पश्चिम बंगाल का विकास कर सकती है और कोई नहीं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश को जब आजादी मिला तब पश्चिम बंगाल देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक था, सुजलाम-सुफलाम भूमि थी, यहाँ से चावल देश के बाकी हिस्सों में जाता था। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय पश्चिम बंगाल का देश की जीडीपी में हिस्सा 25% था लेकिन वामपंथी शासन और ममता सरकार के कुशासन के कारण अब यह कम होकर 4% रह गया है।

उन्होंने कहा कि वामपंथी शासन से पश्चिम बंगाल की जनता को निजात दिलाने के लिए ममता बनर्जी ने माँ, माटी, मानुष का नारा दिया था लेकिन ममता सरकार में पश्चिम बंगाल विकास के मामले में और पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई तो उस वक्त राज्य पर सामूहिक कर्ज लगभग 1,92,000 करोड़ रुपये था जबकि अब यह बढ़ कर 3,50,000 करोड़ रुपये हो गया है, यही बताता है कि तृणमूल सरकार की गलत नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल की क्या दुर्दशा हुई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बम बनाने के अलावा कोई और उद्योग-धंधा रह नहीं गया है, सारे कल-कारखाने बंद हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से ममता बनर्जी का शासन चला है, उससे पश्चिम बंगाल के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ■

कांग्रेस की विफलता के बाद भाजपा का दायित्व है कि वह 'अच्छी राजनीति' की विरासत को आगे बढ़ाए

भाजपा ने 28 जून 2018 को पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के रूप में दिल्ली में अपने मुख्यालय में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा गठित 29 विभागों और प्रकल्पों के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की एक दिन की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी श्री पी. मुरलीधर राव ने की।

यह बैठक 2019 में आने वाले 3 विधान सभा– मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ और आम चुनावों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण रही। इन विभागों में सुशासन और केन्द्र राज्य समन्वय विभाग, नीति अनुसंधान विभाग, मीडिया विभाग, मीडिया सम्बन्ध विभाग, प्रशिक्षण विभाग, राजनीति फीडबैक विभाग, राजनीति कार्यक्रम तथा बैठक विभाग, पुस्तकालय तथा डॉक्युमेंटेशन विभाग, आपदा राहत और सहायता विभाग, अध्यक्ष प्रवास एवं कार्यक्रम विभाग, प्रकाशन तथा साहित्य विभाग, न्यास समन्वय विभाग, चुनाव प्रबंध विभाग, चुनाव समन्वय विभाग, विधि तथा कानूनी कार्य विभाग, पत्रिकाएं और प्रकाशन विभाग, आईटी विभाग, वेबसाइट और सोशल मीडिया विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग तथा आजीवन सहयोग निधि शामिल हैं। ये सभी प्रकल्प और विभाग आने वाले राजनीतिक संग्राम के लिए पार्टी को सशक्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

बैठक में बोलते हुए भाजपा महासचिव तथा प्रशिक्षण प्रभारी श्री पी. मुरलीधर राव ने कहा, ''कांग्रेस ने राष्ट्र को धोखा दिया और वह अच्छी राजनीति के आदर्शों को आगे ले जाने की अपनी जिम्मेदारी में विफल रही। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस में जो मिशन की भावना प्रतिष्ठित थी, अब वह विराजमान नहीं है और उसने अपनी परिवार कम्पनी बना ली है। अब लोग भाजपा की तरफ निहारते हैं तथा भाजपा इसमें विफल नहीं हो सकती है। हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसा तैयार किया गया है जिससे हम न केवल सर्वोत्तम लोगों को आगे आने का बढ़ावा देते हैं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं।

2015 में भाजपा ने प्रशिक्षण महाभियान शुरू किया था और इसके प्रथम चरण में पार्टी ने मंडल, जिला और राज्य स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है और लगभग 10 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया है। दूसरे चरण में पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान सभी मोर्चाओं और विभागों आदि के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया है और इसे प्रशिक्षण का तीसरा चरण कहा जा सकता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम संयोजक श्री महेश शर्मा ने बताया कि यह पार्टी कार्यकर्ताओं की अद्वितीय राजनैतिक प्रशिक्षण योजना है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर पुनर्निर्माण की दिशा में ध्यान देने के लिए कहा है। यह पहली बार है कि भारत में किसी राजनैतिक पार्टी ने इतना भारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। श्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने पहले महासदस्यता अभियान की शुरूआत की जिसमें पार्टी ने 11 करोड़ से अधिक सदस्यों का विश्व रिकार्ड कायम किया। इसके बाद महासंपर्क अभियान के रूप में पार्टी में शामिल सभी नए सदस्यों से संपर्क किया और उन्हें पार्टी की मूल विचारधारा और कार्यपद्धति से परिचित कराया।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में श्री अरविंद मेनन शामिल हैं जो पार्टी के सभी विभागों के समन्वयक हैं। इसमें श्री जगदीप धनकड़ (पूर्व मंत्री एवं विधि विभाग प्रभारी), श्री वी. सतीश (राष्ट्रीय सह महासचिव, संगठन), श्री रविन्द्र साठे, श्री आर. बालाशंकर, श्री सुनील पाण्डे, श्री हेमंत गोस्वामी और डॉ. शिवशक्ति बक्सी (संयोजक, पार्टी पत्रिकाएं एवं प्रकाशन विभाग), श्री अमित मालवीय (आईटी प्रभारी), श्री विजय चौथाईवाला (अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध) और कई अन्य प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। ■

आपातकाल देश के स्वर्णिम इतिहास पर काला धब्बा है: नरेन्द्र मोदी

देश में 43 साल पहले आपातकाल लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 जून को कहा कि एक परिवार के ''स्वार्थी निजी हितों के चलते भारत को जेल में तब्दील कर दिया गया था।" आपातकाल की बरसी पर आयोजित बैठक में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वयं को पुनःसमर्पित करने के लिए मनाए जाने की जरूरत है।

श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल देश के स्वर्णिम इतिहास पर काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपातकाल लगाने जैसे पाप के लिए कांग्रेस की आलोचना करने की खातिर ही आज काला दिवस नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना भी है।

भाजपा के शासन में संविधान, दलितों और अल्पसंख्यकों के खतरे में होने का ''काल्पनिक डर फैलाने" के लिए कांग्रेस की कटु आलोचना करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं सुधर सकती। उन्होंने कहा, ''निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी को बर्बाद किया।"

श्री मोदी ने कहा, ''स्वार्थी हितों के लिए कांग्रेस ने विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर देश को कारागार में बदल दिया था। उनके लिए देश और लोकतंत्र की कोई कीमत नहीं है। अदालत के फैसले के बाद (इंदिरा गांधी) प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बजाए आपातकाल लगा दिया गया। यह लोग संविधान की रक्षा करने की बात कैसे कर सकते हैं।" उन्होंने कहा, ''जब किशोर कुमार जी ने उनके लिए (कांग्रेस के लिए) गाने से इनकार कर दिया तो, रेडियो पर उनके गाने बजाने नहीं दिए जाते थे।"

श्री मोदी ने कांग्रेस पर लोकसभा में 400 से घटकर महज 44 सीटों पर सिमटने के बाद ईवीएम और भारत निर्वाचन आयोग की आलोचना करने के लिए भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ''उन्होंने हालिया कर्नाटक चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए।" उन्होंने उच्चतम न्यायालय के मौजूदा प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की।

श्री मोदी ने कहा, ''उन्होंने (गांधी परिवार) कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और वह जमानत पर बाहर रहेंगे। इसलिए, कांग्रेस ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला लिया।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान की रक्षा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ''संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि वह आम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया है।"

श्री मोदी ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका और कुलदीप नैयर तथा स्टेट्समैन अखबार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ''उनमें से कई हमारे समर्थक भी नहीं हैं। नैयर हमारे आलोचक हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी।" ■

देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय है आपातकाल : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 26 जून को अहमदाबाद में आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा जेल में बंद किये गए लोकतंत्र के प्रहरी मीसा बंदियों और जन संघ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया और लोकतंत्र का गला घोंटनेवाली मानसिकता के लिए कांग्रेस पर जम कर प्रहार किया।

श्री शाह ने कहा कि आपातकाल देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दिवस को काले दिन के रूप में मनाने का निर्णय इसलिए लिया है ताकि देश की जनता एवं भावी पीढ़ी सजग व सतर्क रहें, आपातकाल के दंश को कभी न भूलें और फिर से लोकतंत्र का अपहरण कर देश में आपातकाल लगाने की कोई हिम्मत न कर पाए। उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करके देश की भावी पीढ़ी को लोकतंत्र पर वज्राघात करने का पाप करने वाली कांग्रेस की मानसिकता के खिलाफ जागरूक करें और लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिए सदैव तत्पर रहें।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले अपने ही पुरखों के काले कारनामों को भूल जाते हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान अखबारों, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कुठाराघात किया था और लोकप्रिय गायक श्री किशोर कुमार को भी प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी, लोक अधिकारों और मीडिया एवं न्यायपालिका के अधिकारों की रक्षा के लिए यदि सबसे ज्यादा किसी को प्रताड़ित किया गया तो भारतीय जनता पार्टी (तब जन संघ) एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के खिलाफ सबसे ज्यादा संघर्ष किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी (तब जन संघ) और संघ के कार्यकर्ताओं ने किया था। उन्होंने कहा कि लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी क़ानून और एफआईआर के मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया गया जिसमें लगभग 95 हजार कार्यकर्ता भाजपा और संघ के थे। उन्होंने कहा कि श्री जेपी नारायण, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मोरारजी देसाई सरीखे नेताओं को बिना किसी चार्जशीट के जेल में डाल दिया गया, देश भर में नेताओं की गिरफ्तारी की गई और जनता की आवाज को दबाने का कुचक्र रचा गया। उन्होंने कहा कि आज 19 महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रह कर लोकतंत्र को बचाने वाले पुण्यात्माओं का स्मरण करने का दिन है।

आजादी के बाद भारत के लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने का सबसे पहला प्रयास आपातकाल के रूप में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया था। धारा 356 का दुरुपयोग कर अकारण चुनी हुई सरकारों को गिराने की शुरुआत भी इंदिरा गांधी ने ही किया।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद भारत के लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने का सबसे पहला प्रयास आपातकाल के रूप में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया था। धारा 356 का दुरुपयोग कर अकारण चुनी हुई सरकारों को गिराने की शुरुआत भी इंदिरा गांधी ने ही किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार धारा 356 का दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया और इसमें भी सभी अधिक बार इंदिरा गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के समय ऐसे चाटुकारों और चापलूसों की फ़ौज तैयार हो गई कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष तो यहाँ तक कहने लगे कि 'इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इस इंडिया'। उन्होंने कहा कि सत्ता के मदांध लोगों ने बच्चे तक को गाड़ी से कुचल दिया और किसी ने उफ़ तक न की। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा

कि यह आजाद भारत में पहली बार हुआ था कि देश की प्रधानमंत्री संसद में बैठ तो सकती थीं लेकिन वोट नहीं डाल सकती थी और इसी से बचने के लिए अदालत की अवमानना करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप कर लोकतंत्र का गला घोंटने की शुरुआत की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा स्पष्ट मानना है कि परिस्थितियों और अध्यादेशों से आपातकाल नहीं लाई जाती, यह नेता की मानसिकता से आती है जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र को नहीं मानते, जो आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, वही आपातकाल के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि हमने महज एक वोट से भी सरकार गंवाई है, 13 दिनों में भी सरकार गंवाई है लेकिन कभी आपातकाल के बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तीन बुराइयों परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को देश के लोकतंत्र में प्रविष्ट कराया ताकि अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए लोकतंत्र की जड़ों को खोखला किया जा सके। उन्होंने कहा कि उस समय इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में तीन वरिष्ठ जजों को बाईपास करते हुए एक जज को मुख्य न्यायाधीश घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में कमिटेड ज्यूडिशियरी के सिद्धांत की शुरुआत यदि किसी ने की तो इंदिरा गांधी जी ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विचारों में इतना विरोधाभास है कि यदि अदालत का कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो कांग्रेस के हिसाब से ज्यूडिशियरी अच्छी है लेकिन यदि एक भी फैसला खिलाफ चला जाता है तो वह देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से भी नहीं हिचकिचाती और आज वही कांग्रेस न्यायतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का झूठा और निरर्थक आरोप लगाते हैं जबकि कांग्रेस ने तो संवैधानिक संस्थाओं पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि 26 जून का इतिहास यदि कांग्रेस के नेता अच्छे से पढ़ें तो वे अभिव्यक्ति की आजादी, मजबूत न्यायतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने अपने हिसाब से कई संविधान संशोधन कर संविधान को पंगु बनाने का काम किया लेकिन जनता ने आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर अपनी शक्ति का वास्तविक अहसास करा दिया।

श्री शाह ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि हमने पार्टी में परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की नीति को पनपने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मनीषियों ने कार्यकर्ता आधारित एक ऐसी पार्टी का निर्माण किया जहां एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और गरीब-से-गरीब घर में जन्म लेने वाला एक आम कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की नीति को स्वीकार कर लिया, वह लोकतंत्र को कदापि मजबूती नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन संघ से लेकर आज तक पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए काफी मजबूती से कार्य किया है जहां हर तीन वर्ष पर पंचायत-स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव होते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पार्टी का परिचय उसकी विचारधाराओं, आंदोलनों और उसकी सरकार के कार्यक्रमों से होती है। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर आज तक जन संघ से भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा में हमारी सभी नीतियां देश के हित में बनी हैं और सभी आंदोलन देश की भलाई के लिए किये गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं के केंद्र में देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, आदिवासी, युवा एवं महिलायें ही हैं और हमने विकास को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रबंध किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत हमारे हर मनीषी नेताओं का जीवन निष्कलंक रहा है जिनके

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पार्टी का परिचय उसकी विचारधाराओं, आंदोलनों और उसकी सरकार के कार्यक्रमों से होती है। आजादी से लेकर आज तक जन संघ से भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा में हमारी सभी नीतियां देश के हित में बनी हैं और सभी आंदोलन देश की भलाई के लिए किये गए हैं।

जीवन का क्षण-क्षण और शरीर का कण-कण राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक 'संघर्षमय गुजरात' से आपातकाल के समय उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर देश के नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि 10 सदस्यों से जन संघ के रूप में शुरू हुए सफ़र में आज भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, 330 सांसद हैं, 1500 से अधिक विधायक हैं, 18 राज्यों में सरकारें हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की लोक-कल्याणकारी एवं विकासोन्मुख सरकार है। उन्होंने कहा कि आज हमारा यह दायित्व बनता है कि हम पार्टी के आचार, विचार और संस्कार को और मजबूती देते हुए आने वाली पीढ़ी के हाथों में दें। उन्होंने कहा कि आपातकाल सिर्फ हमारे लोकतंत्र के इतहास में केवल काला अध्याय भर नहीं है, यह नई पीढ़ी के लिए लोकतंत्र को बचाने की सीख लेने वाला दिन भी है। ■

'सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने गरीबों, दलितों को संकट से जूझने और जीतने की हिम्मत दी'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जून को सामाजिक सुरक्षा योजना के देशभर के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बातचीत में चार प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अटल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और वय वंदन योजना शामिल रहीं। प्रधानमंत्री की यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने की आठवीं कड़ी है।

विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए और मजबूती के साथ ऊभरे लोगों से बातचीत पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लोगों को सशक्त कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार की ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जीवन की अनिश्चयताओं से जूझ रहे लोगों को प्रभावी तरीके से न सिर्फ मदद कर रही हैं, बल्कि परिवार को मुश्किल वित्तीय हालात से उबरने में उन्हें मजबूती भी प्रदान कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने गरीबों और वंचितों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में भी बताया। इस कड़ी में उन्होंने गरीबों के लिए बैंक के द्वार खोले जाने, लोगों को बैंक से जोड़ना, छोटे व्यापारियों और उभरते उद्यमियों के लिए पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करना, फंडिंग की व्यवस्था और गरीबों एवं वंचितों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, सबको वित्तीय सुरक्षा के बारे में बताया।

लाभार्थियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 से 2017 के दौरान प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत कुल 28 करोड़ बैंक खाते खुलवाए गए, जो इस दौरान दुनियाभर में खुलवाए गए बैंक खातों का लगभग 55 फीसदी है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि भारत में अब ज्यादातर महिलाओं के बैंक खाते हैं और वर्ष 2014 में 53 फीसदी के मुकाबले देश में बैंक खातों की संख्या 80 फीसदी तक पहुंच गई हैं।

प्रधानमंत्री ने लोगों की संघर्ष गाथा सुनते हुए कहा कि जन हानि की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार ने प्रभावित परिवार को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की हमेशा ही कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लगभग 300 रुपये की छोटी प्रीमियम का भुगतान कर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से लाभ उठाया है।

दुर्घटना कवर करने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना को अपनाया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लोग सिर्फ 12 रुपये का सालाना प्रीमियम का भुगतान कर 2 लाख रुपये तक की दुर्घटना बीमा राशि का दावा कर सकते हैं।

लाभार्थियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने बुर्जुगों की देखभाल से जुड़ी विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल शुरू वय वंदना योजना से लगभग 3 लाख बुर्जुग लोगों ने लाभ उठाया है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोग 10 साल तक 8 फीसदी का तय ब्याज प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के बेहतर जीवन के प्रति प्रतिबद्ध है।

सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की सरकारी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन साल के अंदर तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के तहत 20 करोड़ से अधिक लोगों को लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को यह भी विश्वास दिलाया कि सरकार सभी नागरिकों खासकर गरीबों और वंचितों का कल्याण सुनिश्चित करने की कोशिशों को जारी रखेगी और बेहतर तरीके से उन्हें सशक्त करेगी।

प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने विस्तार से बताया कि जरूरत के समय इन योजनाओं ने कैसे उनके जीवन में मदद की। लाभार्थियों ने इन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया और यह बताया कि ज्यादातर योजनाएं कई लोगों के लिए जीवन में बदलाव का माध्यम बनीं। ■

अब 'बेल गाड़ी' के नाम से जानी जाती है कांग्रेस पार्टी : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 जुलाई को जयपुर में प्रदेश के लिए 13 शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। उसके बाद, उन्होंने भारत सरकार एवं राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के चुने हुए लाभार्थियों द्वारा उठाए गए अनुभवों की एक श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति का अवलोकन किया। इन योजनाओं में कई अन्य योजनाओं के अतिरिक्त, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजनाएं आदि शामिल थीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि इन दिनों लोग कांग्रेस पार्टी को बेल गाड़ी के नाम से पुकारने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जमानत पर बाहर हैं। श्री मोदी ने कांग्रेस द्वारा सेना की क्षमताओं पर सवाल उठाने की आलोचना करते हुए कहा कि देश के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।

श्री मोदी ने 7 जुलाई को जयपुर के 'अमरुदों का बाग' में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने किस नीयत से काम किया और इसी नीयत का परिणाम है कि कांग्रेस को आजकल कुछ लोग बेल गाड़ी बोलने लगे हैं। कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले कई नेता और कई पूर्व मंत्री आजकल 'बेल' पर यानी जमानत पर हैं। लेकिन जनता ने जिस भरोसे के साथ कांग्रेस की संस्कृति को नकारा है और भाजपा को जनादेश दिया है उस भरोसे को दिनोंदिन मजबूत करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि राजनैतिक विरोधियों ने सेना की क्षमता पर सवाल उठाने का पाप किया है। यह पहले कभी नहीं हुआ, राजस्थान और देश के लोग ऐसी राजनीति करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिनको परिवार की राजनीति करनी हो करें, लेकिन देश की रक्षा और स्वाभिमान को शिखर पर ले जाने का हमारा निश्चय अटूट है और हमारी नीतियां साफ हैं। यही कारण है कि जो 'वन रैंक वन पेंशन' का मुद्दा सालों से अटका हुआ था इस सरकार ने उसका भी समाधान किया।

वहीं श्री मोदी ने विकास को अपनी सरकार का एक मात्र एजेंडा बताते हुए कहा कि पांच करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जा चुका है तथा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। श्री मोदी ने किसानों की फसल का समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणी से ज्यादा वृद्धि करने के फैसले के बाद राजस्थान में अपनी पहली सभा में सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए बीज की खरीद से फसल की बिक्री तक का प्रबंध करने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि फसल की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य करने से किसानों को काफी फायदा हुआ है। खरीद प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए है। राजस्थान सरकार समर्थन मूल्य पर ग्यारह हजार करोड़ रुपए की खरीद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर 70 साल तक देश पर राज किया लेकिन कांग्रेस अपने ही समुदाय और परिवार में सिमट कर रह गयी है।

भाजपा का एक ही धर्म है, वो है जनता की सेवा: वसुंधरा राजे

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की गरीबी हटाओ, इंदिरा आवास व दूसरी योजनाओं पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में गरीबी-कल्याण की सिर्फ बातें हुई। धरातल पर कुछ नहीं हुआ। बल्कि कांग्रेसी अपने परिवार और कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाने में लगे रहे। प्रधानमंत्री मोदीजी ने देश के गरीबों की पीड़ा को समझा। उनके लिए कई लाभकारी योजनाओं को लागू किया। जनधन, मोबाइल, आधार के माध्यम से गरीबों का लाभ सीधे उनके खातों में पहुंचाया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। भाजपा ने जनता की सेवा को ही अपना धर्म माना। ■

प्रधानमंत्री ने रखी संत कबीर अकादमी की आधारशिला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 जून को उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के मगहर पहुंचे और महान संत एवं कवि कबीर दास की 500वीं पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संत कबीर समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और संत कबीर मजार पर चादर चढ़ाई। प्रधानमंत्री ने संत कबीर गुफा का भी दर्शन किए और संत कबीर अकादमी की आधारशिला की पहचान के रूप में एक पट्टिका का अनावरण किया। संत कबीर अकादमी महान संत के उपदेशों और विचारों को फैलाने पर जोर देगा।

इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी भी मौजूद थे।

इस मौके पर जन सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मगहर की पवित्र भूमि पर महान संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते ही मेरी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई, यह वह जगह है, जहां संत कबीर, गुरू नानक और बाबा गोरखनाथ ने आध्यात्मिक चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 24 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला संत कबीर अकादमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय भाषाओं और लोक कलाओं के साथ ही संत कबीर की महान विरासत का संरक्षण करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संत कबीर भारत की आत्मा के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर ने जाति के बंधनों का तोड़ा और आमजन की भाषा में अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि संत कबीर के उपदेश नये भारत के दृष्टि को

आकार देने में मदद करेंगे।

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि संत कबीर का जीवन, शब्द एवं कर्म 'वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन की तर्ज पर है। उन्होंने कहा कि संत कबीर की अतुलनीय विरासत ने समाज के सभी तबकों को एकजुट किया है और हम उनकी शिक्षाओं में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संदेश को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें यह भी कहा कि संस्कृति मंत्रालय उन महान पुरुषों के जीवन और कर्मों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, जिन्होंने भारत को एक महान राष्ट्र बनाया है। ■

इंडियन सोशल रेस्पोंसिबिलिटी नेटवर्क (आई. एस.आर.एन) द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित सतत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का प्रलेखन और संकलन नामक शीर्षक का अध्ययन आरम्भ किया जा रहा है, जिसका प्रयोजन अंत्योदय आधारित सतत विकास के सफल कार्यप्रणाली को आदर्श के रूप में प्रोत्साहन और उसकी पुनरावृत्ति कर रहे अधिकाधिक संगठनों / संस्थानों / व्यक्तियों के कार्यों को लेखबद्ध करने और साझा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित व एकत्र कर उन्हें संकलित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

संगठनों / संस्थानों / व्यक्तियों से अनुरोध है कि "अंत्योदय" अर्थात "आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति (वंचित/ शोषित / प्रताड़ित) के उत्थान" की संकल्पना पर आधारित व संचालित अपने कार्य की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करें । इस सम्बन्ध में नियुक्त निर्णायक समिति द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रिया से चयनित सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को इस अध्ययन की रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा, जो की राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होगी।

इच्छुक संगठन/ संस्थान/व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए लिंक https://goo.gl/forms/XaHXKRsKXFHSvKU72 को देखें व प्रारूप को भर कर अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2018 तक भेजें ।

यह अध्ययन रिपोर्ट आई.एस.आर.एन द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जाएगी ।

डॉक्टर परिवार के मित्र सरीखे हैं: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को 'मन की बात' कार्यक्रम (45वीं कड़ी) के दौरान कहा कि मां हमें जन्म देती है, तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। डॉक्टर की भूमिका केवल बीमारियों का इलाज़ करने तक सीमित नहीं है। अक्सर डॉक्टर परिवार के मित्र की तरह होते हैं।

उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर के पास मेडिकल एक्सपॅर्टीज़ तो होती ही है, साथ ही उनके पास जनरल लाइफ स्टाइल ट्रेंड्स के बारे में, उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबके बारे में गहरा अनुभव होता है। भारतीय डॉक्टरों ने अपनी क्षमता और कौशल से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनायी है। मेडिकल प्रोफेशन में महारत, हार्डवर्किंग के साथ-साथ हमारे डॉक्टर काम्प्लेक्स मेडिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जाने जाते हैं।

साथ ही, श्री मोदी ने यह भी कहा कि संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। यही उनके आदर्श थे। उनकी रचनाओं में हमें यही आदर्श देखने को मिलते हैं और आज के युग में भी वे उतने ही प्रेरक है। उनका एक दोहा है:-

कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर।
जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर ।।

मतलब सच्चा पीर संत वही है जो दूसरो की पीड़ा को जानता और समझता है, जो दूसरे के दुःख को नहीं जानते वे निष्ठुर हैं। कबीरदास जी ने सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया था। वे अपने समय से बहुत आगे सोचते थे। उस समय जब विश्व में अवनति और संघर्ष का दौर चल रहा था, उन्होंने शांति और सद्भाव का सन्देश दिया और लोकमानस को एकजुट करके मतभेदों को दूर करने का काम किया ।

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस 21 जून को चौथे 'योग दिवस' पर एक अलग ही नज़ारा था। पूरी दुनिया एकजुट नज़र आयी। विश्व-भर में लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ योगाभ्यास किया। ब्रुसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट हो, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो, जापानी नौ-सेना के लड़ाकू जहाज़ हों, सभी जगह लोग योग करते नज़र आए।

श्री मोदी ने कहा कि सऊदी अरब में पहली बार योग का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और मुझे बताया गया है कि बहुत सारे आसनों का प्रदर्शन तो महिलाओं ने किया। लद्दाख की ऊंची बर्फीली चोटियों पर भारत और चीन के सैनिकों ने एक-साथ मिलकर के योगाभ्यास किया। योग सभी सीमाओं को तोड़कर, जोड़ने का काम करता है। सैकड़ों देशों के हजारों उत्साही लोगों ने जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग या लिंग हर प्रकार के भेद से परे जाकर इस अवसर को एक बहुत बड़ा उत्सव बना दिया। यदि दुनिया भर के लोग इतने उत्साहित होकर 'योग दिवस' के कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे तो भारत में इसका उत्साह अनेक गुना क्यों नहीं होगा?

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को गर्व होता है, जब सवा-सौ करोड़ लोग देखते हैं कि हमारे देश के सुरक्षा बल के जवान, जल-थल और नभ तीनों जगह योग का अभ्यास किया। कुछ वीर सैनिकों ने जहां पनडुब्बी में योग किया, वहीं कुछ सैनिकों ने सियाचीन के बर्फीले पहाड़ों पर योगाभ्यास किया। वायुसेना के हमारे योद्धाओं ने तो बीच आसमान में धरती से 15 हज़ार फुट की ऊंचाई पर योगासन करके सबको स्तब्ध कर दिया। देखने वाला नज़ारा यह था कि उन्होंने हवा में तैरते हुए किया, न कि हवाई जहाज़ में बैठकर के। स्कूल हो, कॉलेज हो, दफ्तर हो, पार्क हो, ऊंची ईमारत हो या खेल का मैदान हो, सभी जगह योगाभ्यास हुआ।

श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद का एक दृश्य तो दिल को छू लेने वाला था। वहां पर लगभग 750 दिव्यांग भाई-बहनों ने एक स्थान पर, एक साथ इकट्ठे योगाभ्यास करके विश्व कीर्तिमान बना डाला। योग ने जाति, पंथ और भूगोल से परे जाकर विश्व भर के लोगों को एकजुट होकर करने का काम किया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के जिस भाव को हम सदियों से जीते आये हैं। हमारे ऋषि, मुनि, संत जिस पर हमेशा जोर देते हैं, योग ने उसे सही मायने में सिद्ध करके दिखाया है। मैं मानता हूं कि आज योग एक वैलनेस रिवोल्युशन का काम कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि योग से वैलनेस की जो एक मुहीम चली है, वो आगे बढ़ेगी। अधिक से अधिक लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनायेंगे। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

संत कबीर नगर जिला (उ.प्र.) स्थित मगहर गांव में संत कबीर की समाधि पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर गन्ना किसानों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली स्थित संसद के केन्द्रीय कक्ष में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जयंती (6 जुलाई) पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जयपुर (राजस्थान) में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करते एवं किसानों से हल प्राप्त करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथिः (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघरः लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

किसानों की आय बढाने के लिए सरकार ने उठाया महत्वपूर्ण कदम

खरीफ 2018-19 के लिए MSP को उत्पादन की लागत का डेढ़ गुना या उससे ज्यादा बढ़ाया

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

जिंस		2018-19 (रुपये प्रति क्विंटल)		
खरीफ फसलें	किस्म	उत्पादन लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	उत्पादन लागत* पर प्रतिशत लाभ
धान	सामान्य	1166	1750	50.09
	ग्रेड ए		1770	
ज्वार	हाइब्रिड	1619	2430	50.09
	मालदांडी		2450	
बाजरा		990	1950	96.97
रागी		1931	2897	50.01
मक्का		1131	1700	50.31
अरहर (तूर)		3432	5675	65.36
मूंग		4650	6975	50.00
उड़द		3438	5600	62.89
मूंगफली (छिलका सहित)		3260	4890	50.00
सूरजमुखी बीज		3592	5388	50.01
सोयाबीन		2266	3399	50.01
तिल		4166	6249	50.01
रामतिल		3918	5877	50.01
कपास	मध्यम रेशा	3433	5150	50.01
	लम्बा रेशा		5450	

* इसमें सभी भुगतान की गयी लागतें शामिल हैं जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम / मशीन श्रम, पट्टाभूमि के दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पम्प सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल / बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।